12.59 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75—*Contd.*

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE —*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now resume the discussion on the Demands of the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH). We have 1 hour and a few minutes left. There are still a few speakers on the opposition and a good number on our side who want to speak. I have talked to the leaders of the opposition parties. Subject to your orders, the time may be extended by 2 hours.

MR DEPUTY-SPEAKER· If the House has no objection, I can't have any objection because my big obstacle of having a tussle with the members will be reduced to that extent. Shri K C. Pandey

14.00 hrs.

श्री कृष्ण चन्द्र पाडे (खलीलाबाद) माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा और समाजकल्याण मंत्रालय की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, इस देश को आजाद हुए 27 वर्ष होने जा रहे है लेकिन आज तक इस देश की शिक्षा नीति मे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया । कई आयोग और कई समितियो का गठन हुआ, सिफारिशे आई, लेकिन उन पर पालन नही किया गया । जिस का परिणाम है कि आज देश मे छात्र असन्तोष और शिक्षक असन्तोष बढता ही जा रहा है । आप जानते हैं कि आज देश में जो भी शिक्षा-प्रणाली है उस को हम भारतीय शिक्षा प्रणाली नही कह सकते, क्योंकि वही पुरानी अंग्रेजों की शिक्षा नीति का अक्षरश. पालन किया जा रहा है, जो देश में बाबू पैदा करने के लिए बनाई गई थी और आज देश में हमारे शिक्षा मंत्री जी भी बाबू ही पैदा कर रहे हैं । मैं आप के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे दिन लद गये, अब आप को छात्रो, अध्यापकों और बेरोजगारी की चुनौती को स्वीकार करना चाहिये, शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिये । इस सम्बन्ध में गीता में भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है —

> वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
> नवानि गृहणाति नरोऽपराणि ।
> तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि
> संयाति नवानि देही ।।

अगर देश को मजबूत करना है, अगर देश की बेरोजगारी को दूर करना है तो आपको यथार्थवादी नीति अपनानी पडेगी और शिक्षा को रोजगार बनाना पडेगा । यदि ऐसा नही किया गया तो जैसा हमारे बुजुर्ग सदस्य माननीय विभूति मिश्र जी ने कल कहा था—यह चुनौती है छात्रो को, अगर छात्रों की समस्याओं का समाधान नही किया गया तो आने वाला भविष्य इस पीढ़ी को बरदाश्त नही करेगा । मै पुन माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं —आप इस शिक्षा नीति को उठा कर हिन्द महासागर मे दफना दे । अगर कालिजो को एक साल के लिए बन्द करना पडे, अगर विश्वविद्यालयो को एक साल के लिए बन्द करना पडे तो बन्द कर दीजिए, लेकिन बैठ कर एकाग्र चित से शिक्षा नीति को बनाइये, जिस से बेरोजगारी न बढ़े । आप के जो भी शिक्षित नौजवान शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकले उन का सदुपयोग किया जाये ।

आज कल की बढ़ती हुई बेरोजगारी की पूरी जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षा मंत्रालय पर है और यह बेरोजगारी तभी दूर की जा सकती है जब रोजगारपरक शिक्षा नीति हो

इस के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं—जोकभी शिक्षा प्रणाली बनाई जाय वह यथार्थवादी होनी चाहिए व्यवसायपूरक होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के नैतिक चरित्र में भी सुधार हो।

आज देखा जा रहा है कि स्वतन्त्रता के बाद देश के नैतिक चरित्र का जो ह्रास हुआ है—उस की जिम्मेदारी भी दूसरे विभागो पर नही है उस की जिम्मेदारी भी एक मात्र शिक्षा मन्त्रालय पर है। जब तक जिस देश की शिक्षा नीति मजबूत नही रहेगी सुदृढ नही रहेगी उस देश की भावनाओं को ले कर चलने-वाली नही होगी बेरोजगारी बढती जायगी जनता का आक्रोश छात्रो का आक्रोश बढ़ता जायगा। मैं अपील करना चाहता हूं आप लोग एकाग्र चित्त हो कर बैठ कर शिक्षा नीति पर पुन विचार करे और बदले।

आज देखा जा रहा है कि हमारे पढ लिखे छात्र भाई रोजगार और नौकरी के लिए लखनऊ और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन को रोजी नही मिलती। हार कर वे विद्यालयो और विश्वविद्यालयो मे जाते हैं और वही से इस देश मे विद्रोह की भावना भडक रही है।

मै इस मौके पर एक निवेदन करना चाहता हू —राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और परीक्षा नीति पर पुन विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयो की परीक्षाओं का केन्द्रीयकरण होना चाहिए। इस केन्द्रीयकरण से एक लाभ होगा कि राष्ट्र मे प्रदेश मे जो लडाई चल रही है एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के लोगो से बिलगाव चल रहा है वह कम होगा और देश मे राष्ट्रीय जागृति आयेगी लोगो मे एकता आयेगी और यदि आप परीक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो वह भी सुधर सकेगा। राष्ट्रीय एकता को बल देना चाहेंगे तो वह भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार करे और राष्ट्रीय स्तर पर सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का केन्द्रीयकरण किया जाय। इस से सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

मैं यह भी अपील करना चाहता हूं—शहर में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बडे लम्बे-चौडे अनुदान दिये जाते हैं लेकिन देहात मे बसने वाले गरीब मजदूर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा इस लिए नही दे पाते कि वे दिल्ली से बहुत दूर बसते हैं। जो सुविधायें आप दिल्ली नगर के छात्रो को दे रहे हैं वे देहात के विद्यार्थियों को भी दी जाय जिस से इस देश के गरीब मजदूर अपने को समझ सके कि 27 वर्ष की आजादी के बाद हमारे बच्चो को अच्छी शिक्षा मिल रही है। शहरों मे देखा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे-छोटे बच्चो के लिए मोन्टेसरी स्कूल खुले हुए हैं बसें आती हैं और बच्चों को ले जाती हैं लेकिन देहातो में गरीब मजदूरों के बच्चों की स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं चाहता हू कि प्रत्येक ब्लाक लेवल पर ऐसे स्कूल खोले जाय जिस के लिए आप ने आश्वासन भी दिया था। ये छोटे छोटे स्कूल सरकार को चलाने चाहिए और वहां के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए।

शिक्षा मन्त्रालय ने बहुत से महापुरुषों की जन्म शताब्दि मनाई है। महात्मा बुद्ध से ले कर निकोलस तक जन्मशताब्दि मनाई गई लेकिन मैं देख रहा हूं महात्मा तुलसी जिन का हिन्दी साहित्य मे अनुपम योगदान है जिस तुलसी ने राम की कथा को ले कर राम को देश और विदेश में अमर कर दिया उस तुलसी की आज कल चतुःशती मनाई जा रही है उस में शिक्षा मंत्रालय अत्यन्त

(श्री कृष्णा चन्द्र पांडे)

निराशा दिखा रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय उस तरफ ध्यान दे क्योंकि महात्मा तुलसी का हिन्दी साहित्य में प्रधान स्थान है।

एक अपील और करना चाहता हूं — छात्र असन्तोष पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने श्री एन० सी० पराशर संसद सदस्य के प्रस्ताव पर एक उपसमिति बनाई थी उस कमेटी ने क्या किया अभी तक कोई जानकारी हम लोगों को नहीं हुई है।

तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहता हू कि ऐसी कमेटिया जो बनाई जाये उस पर विचार करना चाहिए और छात्र असंतोष जो बढ़ रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज देश मे छात्र असन्तोष को भड़काने की कोशिश कुछ प्रतिक्रियावादी लोग कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि विद्यालयो और विश्वविद्यालयो को राजनीतिज्ञों के चगुल से बचाये और उनको एक स्वस्थ परम्परा जो इस राष्ट्र की परम्परा रही है उस पर ले जाये। आज देखा जा रहा है कि बिहार मे जयप्रकाश नारायण जी जो सर्वोदय नेता हैं क्रान्ति पर उतर आये हैं और हमारे विद्यार्थी भाइयों को भड़काना आरम्भ कर दिया है। मैं अपने देश के समस्त छात्र भाइयों से अपील करना चाहता हू कि वे प्रतिक्रियावादी एव राजद्रोही तत्वो से सावधान हो कर देश को मजबूत बनाने के लिए देश को एक करने के लिए काम करें जिससे इस देश का निर्माण सम्भव हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं श्री यादवजी जो कि जनसघ के सदस्य हैं उनसे भी अपील करना चाहता हू कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल करके छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें न कि उनको उकसा कर विद्रोह करने के लिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इन अनुदानों की मागों का समर्थन करता हू।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : उपाध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की मागों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा और समाज कल्याण विभाग ठीक उसी तरीके से शिक्षा देने के लिए और लोगो का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है जैसे कि रेडियो और ब्राडकास्टिंग विभाग है। ब्राडकास्टिंग विभाग का भी बच्चों युवकों तथा बड़ी उम्र के नर-नारियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी बहुत ऊंची है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: What the Minister of Information and Broadcasting said was that he would like his Ministry to be upgraded to the level of the Ministry of Education. Now, here, you say that it should be treated as important as the other one.

श्री मुल्की राज सैनी : मैं तो कम्पेरीजन कर रहा हू कि ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री से ज्यादा एजूकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षा विभाग को ज्यादा धन मिलना चाहिए और उसकी लेविल में इसको ऊंचा होना चाहिए—मेरा पहला सुझाव तो यह है।

दूसरे मुझे यह निवेदन करना है कि आज 27 साल के बाद भी देश में सारे बच्चों को शिक्षा देने की जो सरकार की जिम्मेदारी है वह पूरी नहीं हुई है। प्राइमरी स्टेज पर भी पूरी नहीं हुई है और उसके पश्चात माध्यमिक स्टेज में पूरी नहीं हुई है। इसके लिए धन चाहिए इसके लिए योजनायें चाहिए इसके लिए शक्ति चाहिए और वह जरूर मिलनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि पांडे जी ने कहा बहुत बड़ी खाई है। ऊंची आय वालों के बच्चों के लिए मान्टेसरी स्कूल हैं नर्सरी स्कूल हैं और फैन्सी स्कूल हैं जहां पर तीन सौ चार सौ या पांच सौ रुपया महीने में एक बच्चे पर वह खर्च करते हैं। वहां पर उनको अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है जबकि दूसरी ओर देश के 80-90 प्रतिशत गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है या शिक्षा कतई नहीं मिलती हैं। तो इस खाई को दूर करना चाहिए और सभी को प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा शुरू में मिलनी चाहिए।

एक बात जो बहुत महसूस की जा रही है वह है छात्र असंतोष। इस छात्र असंतोष को दूर करने के लिए शिक्षा नीति के अन्दर ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिनको माननीय सदस्य यहां पर कहते रहे हैं। हम सुनते भी रहे हैं कि शिक्षा में परिवर्तन होगा शिक्षा में परिवर्तन होना भी चाहिए लेकिन वह परिवर्तन कौन करेगा वह परिवर्तन कब होगा और कैसे होगा वह बात सामने नहीं आ रही है और न ही उसका समय आ रहा है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र शिक्षा की नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में बेरोजगारी फैलती है। इसके अलावा अभी बाबू तैयार करने की जो नीति कही गई है तो अब बाबू तैयार नहीं हो रहे हैं बल्कि दादा तैयार हो रहे हैं जो जा कर समाज में नेतृत्व करते हैं। वह दादा लोग कौन हैं? वे उन्हीं ऊंचे घरों के लड़के हैं जो कि गरीबों के लड़कों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वे घर में भी रेडियो ट्रांजिस्टर से दादागिरी सीखते हैं और फिर स्कूल कालेजों में दादागिरी करते हैं। तो इस बात को भी रोकना चाहिए। इसके लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। नर्सरी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है उसी प्रकार गरीबों के बच्चों की शिक्षा के स्तर को उचा उठाना है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो पब्लिक स्कूल हैं उन को बन्द कर देना चाहिए कम से कम समय तक के लिए जब तक कि सभी बच्चों को ऊंची शिक्षा न मिल जाये। आज जो फैन्सी स्कूल हैं उनकी मोनोपली हो गई है। वहां पर ऊंचा रोजगार प्राप्त करने ऊंची कुर्सियां प्राप्त करने की मोनोपली बड़े घरानों में आ गई है जिस के बच्चे उन फैन्सी स्कूलों में पढ़ते हैं।

श्री सूरज पांडे (गाजीपुर) : वह बन्द नहीं होंगे।

श्री नुस्कीराज सैनी आज नहीं होगा तो कल होगा लेकिन इसको करना ही होगा। कांग्रेस का प्रोग्राम है कि यह होगा। जब आपका सहयोग मिलेगा तब यह होगा।

जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है उसमें बहुत सारी मदें दी गई हैं और बहुत सारे कार्यालय खोले गए हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केन्द्रीय शिक्षा विद्यालय संगठन केन्द्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—इस प्रकार से यह बहुत

[श्री मुख्तीराम सैनी]

सम्बंधी लिस्ट है और इनको देख कर हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह सारा का सारा शिक्षा और समाज कल्याण बोर्ड का पैसा सारे निदेशालय और यह सारे संगठन ठीक तरह से काम करें तो शायद हमें किसी प्रकार की आलोचना करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेन्टेशन है उस के अन्दर ढिलाई है उसमें खराबी है जिसकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

इसमें जैसे आई टी है जो तकनीकी आधार पर इंजीनियर्स तैयार करती है और दूसरे टेक्निकल पर्सोनेल तैयार करती है विशेष तौर से दिल्ली का जो आई आई टी है उसकी तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास इसके तथ्य हैं, मैंने चिट्ठियों के जरिए से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नही। लगभग दो वर्ष पूर्व संसद के एक माननीय सदस्य ने दिल्ली स्थित आई आई टी में व्याप्त मीषण भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं जनता के पैसे की नाजायज रूप से बर्बादी के ऊपर एक प्रेस कान्फ्रेंस में अपने विचार रखे थे। तत्पश्चात संसद में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी एवं एक पी ए सी का गठन कर आई आई टी के एकाउन्टस की जाच कर ई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी संसद मे प्रस्तुत की थी। पता नही सरकार ने उस पर क्या किया ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि उस रिपोट के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? मैंने इस विषय को लेकर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान अपने पत्र दिनांक 26-72 दिनांक 6-7-72 एव दिनांक 7-3-73 द्वारा आई आई टी में चल र सामन्तवादी रवैये की ओर आकृष्ट कराया था जिसमें कुछ व्यक्तियों को नाजायज रूप से सताया जा रहा है एवं कुछ अन्य व्यक्तियों की गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे कर और उनके काले कारनामों पर पर्दा डालकर पदोन्नति की जा रही है। ठीक उसी तरह का मामला है मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैंने पत्र में दे रखा है जैसे कि पूसा इन्स्टीटयूट में मजबूर हो कर एक इंजीनियर शाह साहब को आत्महत्या करनी पड़ी थी। दिनांक 21-9-73 को मैंने स्वयं मंत्री महोदय से मिल कर उन्हें पूर्ण विवरण से अवगत कराया और उनसे यह आश्वासन भी प्राप्त किया कि वे फाइल मंगाकर इस मामले की स्वयं जांच करेंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों एवं एक वरिष्ठ मंत्री महोदय ने भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था परन्तु खेद है कि अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नही हुई। मैंने संस्थान के चेयरमैन को भी एक चिट्ठी दिनांक 8-8-73 को लिखी थी और मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा पत्र संस्थान के डायरेक्टर को भेज दिया गया है। डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि संस्थान में इस प्रकार के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। जो उचित और जिन के हक हैं उन को हक नही मिल रहा है। जिन का हक नहीं है उन को ऊचा उठाया जा रहा है और उन को ऊंचे ग्रेड दिये जा रहे है। पत्र को पढ़ कर ऐसा आभास हुआ है कि संस्थान के अधिकारी दुश्चरित्र एवं बेइमान लोगो के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का प्रयास करते रहे हैं। मैंने चेयरमैन के पत्र की एक प्रति माननीय मंत्री महोदय को अपने पत्र दिनांक 18-1-74 के साथ संलग्न कर के उन से निवेदन किया कि वे अपने 21-9-73 को दिये गये आश्वासन के अनुसार मामले की जाच करें उस पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिस का कोई उत्तर मुझे प्राप्त नही हुआ है।

चेयरमैन के पत्र के उत्तर में मैंने पूर्ण रूप से विस्तृत विवरण देते हुए एक पर

18-2-74 को लिखा था और उस का रिमाइन्डर भी 19-3-74 को भेजा है जिस का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त संस्थान में जहां देश के भावी इंजीनियरों का निर्माण हो रहा है और जिस पर सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है कई कई दिनों तक बिजली एवं पानी गायब रहता है। पी० ए० सी० की रिपोर्ट के अनुसार उक्त संस्थान में बिजली का केबिल आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदा गया है। और भी काफ़ी सुरक्षात्मक प्रबन्ध रहते हुए बिजली एवं पानी का कई कई दिनों तक गायब रहना दुर्भाग्य की बात है। ज्ञात हुआ है कि एक कर्मचारी द्वारा संस्थान के बिजली घर में गड़बड़ी पैदा कर छात्रावास को काफ़ी समय तक अन्धकार में डुबो दिये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी संस्थान के डायरेक्टर ने उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

लगभग दो वर्ष पूर्व संस्थान ने चार सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया था जिस के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को बराबर ओवरटाइम दिया गया परन्तु उन में से अभी तक एक भी सब-स्टेशन पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार वहां सरकारी पैसे का अपव्यय कर के उस से कुछ विशेष व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। संस्थान के कर्मचारियों द्वारा सरकारी सामान को बेचने और उससे अनुचित धन प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी ने डायरेक्टर आज तक न तो उस मामले की जांच ही करायी और न उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है। इस कुकार्य के लिए शिक्षा मंत्री को 21-9-73 को मैं सूचित कर चुका हूं। मैं बगैर नाम लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन को आई आई टी में 1966 में नियुक्त किया गया था और आज भी वह 250-470 के स्केल में चल रहे हैं। जब कि उन्हीं के साथी दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो 28-10-63 को आये और उन्हें .....

MR. DEPUTY SPEAKER: Further details you can pass on to the Minister.

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) यह सब लिख कर हम को दे दो दीजिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: All these details you can give to the Minister. Now that you have mentioned it, the Minister will give you the reply. Let him look into it and give you a reply.

श्री मूलकी राज सैनी : इतनी उच्च शिक्षा वाले स्थान पर जहां जिम्मेदार लोग है वहां पर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो संस्था का काम ठीक नहीं चल सकता और सरकार का जो बजट खर्च होता है वह बेकार जाता है। इसलिए मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करता कि वह मेरी जो शिकायत है पूरी उस को पर्सनल देखें ताकि गड़बड़ न हो सके और जिन के साथ ऐसा हुआ है उनके साथ न्याय हो सके।

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur): Education is a vast subject and the time at my disposal is very limited. Therefore, I will confine my remarks to certain aspects only.

In the Draft Fifth Five Year Plan we have seen that emphasis has been given on primary education. But even there, a certain percentage of students in the age group of 6—11 will remain outside the operation of the scheme of education. This is more so in respect of girl students. Therefore, I would

[Shri Biswanarayan Shastri]

suggest that more and more emphasis should be given on primary education so that during the period of the Fifth Five Year Plan all the children of this age group may have their education.

It is the knowledge of all members here that there is a demand for allocating 12% of the Budget for education, but we were disappointed to see that the percentage of the budget for education is much lower than the 12% and there is every cut on every pretext.

For example in the last financial year there were cuts on the different aspects of education on the pretext of economy. I do not deny that there is need for economy but this should not be applied to educate indiscriminately. Because, education, as we say always, is a nation-building project. Education should not be considered as a wasteful expenditure or unproductive expenditure because it is just like a foundation of a big building. If the foundation is not stable the building cannot be built up; there cannot be a 4-storey or 5-storey building without proper foundation. There cannot be a good citizen without proper foundation in education.

So far as languages are concerned we have switched over to the regional language as medium of instruction. There is some encouragement from the Government for preparation of text books in the regional languages to be prescribed for the students studying in the different universities. It is a good thing. But more emphasis should be there in other respects also for development of those regional languages. Otherwise as a national language, Hindi cannot grow. Because, there must be proper coordination among all the regional languages so that Hindi can take its proper place.

In this context I would like to plead and emphasise the case of Sanskrit, Urdu and Arabic which have no definite region or area as such. The Government of India of course has done something for all the languages but still more is awaited. So far as Sanskrit is concerned, the Rashtriya Sanskrit Sansthan has suggested and submitted a proposal to the Government for the establishment of a Central Manuscript Library which was very essential. Sanskrit is not to be viewed from a communal or religious point of view. It is a national language. We have seen even in Communist China they have printed Buddhist sanskrit texts. Some of them are translated into Chinese also and we are making use of them nowadays. Therefore Central Sanskrit Manuscript Library when established at Delhi will be an international property. I would urge upon the Minister to take immediate steps in this regard.

So far as the University Grants Commission is concerned, my experience is very disappointing. The University Grants Commission has been turned into a grant-giving institution as if they are meant for and their main purpose is to distribute grants to the different universities and colleges and to fix up plans and sanction projects for constructing the hostels and College buildings. *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY SPEAKER: The two Ministers are adding force and volume to your speech! You are too soft-spoken.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI: University Grants Commission has done nothing so far which can be appreciated by the people. They may produce certain essays, certain thesis, sitting in their offices which are quite unrealistic to the mass of the people and to the educated people as well. Therefore I would urge upon the Minister to see that the University Grants Commission creates an atmosphere and takes initiative in this regard to reform the examination system practically which will be realistic and not by producing 100 page essay. They should take initiative for advancement of learning. It is repeatedly stated that they are going

to take steps for avoiding duplication of research and other higher standards of education in univerities. What is the result? In a particular State, for instance, there are seven, eight or nine universities where the same subjects are taught in all the universities. The research and other facilities for higher stndard of education that are there are not to the satisfaction. If a selective attitude has been taken by a particular university to specialise in a particular field, then that university will cater to the needs not only of that states but also will cater to the country as a whole. Such a selective attitude should be taken. U.G.C. should take the initiative in the matter.

So far as disbursement of grant is concerned, I have to complain that the rural colleges or, the colleges, situated in the rural areas, have not received the same attention as the colleges situated in urban areas do receive. Because the people or the representatives from urban area are more vocal, more grants are given to those institutions situated in those areas. So far as the amount of grant is concerned, there is a great disparity. For example, a college in a rural area, for construction of a hostel, will receive Rs. 40,000 or 50,000 or so as grant while a college situated in an urban area may receive Rs. 2 lakhs or 3 lakhs or even more. That disparity is still there. Even that small amount is not forthcoming to the rural colleges. I should say that there should be no discrimination and more liberal attitude should be taken to the colleges situated in the rural areas.

I would also like to refer to the cultural affairs. In the budget estimate, we see that a sum of Rs. 11 crores has been provided for cultural activities including archeology. Government of India have three academies and one International Centre. So far as the academies are concerned, the grant given to them is inadequate. The Sahitya Academy has to execute programmes in different languages. But, the grant for this institution is about Rs. 7 lakhs or something like that. If I am not wrong, 83 per cent of the grant is spent on administration alone. Therefore, there remains very little for the programme to be executed. I would suggest that for the schemes submitted by the Academy, more grants should be made available, particularly, to carry out programmes in different regional languages. Sangeet Natak Academy and Lalit Kala Academy are more fortunate in this respect. These two institutions are receiving higher amounts of grants than the Sahitya Academy. Buut, these two Academies have not reached the rural people so far. We have a vast majority of the people in our countryside, particulary tribals where there are folk dances and other dances. Sangeet Natak Academy has not done anything so far to bring in the experts or artistes from among them to the capital and produce them before the vast galaxy of the capital. If the activities are confined only to the States capitals and to the sophisticated areas, then, I should say, it is a capitalist attitude and it has nothing to do with the present structure of our society.

I would urge upon the Ministry to see hat Sangit Natak Academy and Lalit Kala Academy do something for the culture which is abundant in our countryside. They should know the Rustic India. Rustic India has many things to contribute for the cultural development of our country. In this respect also I would refer to cultural exchanges. There is a cultural exchange programme and the Government of India have entered into an agreement with different foreign countries for sending delegations. But the selection of the delegations is not satisfactory because the same group of persons have been selected and the fortunate ones visit those foreign countries. In the matter of selection of members of cultural delegations, consideration should be given to all parts of India because there are certain persons who are knowledgeable in art,

[Shri Biswanarayan Shastri]

culture, dance and different aspects of arts in different parts of India in different communities.

So far as distribution of grants to voluntary institutions is concerned, last year it has not been distributed due to measures of economy. I hope this year they will renew the scheme. Under this scheme, grants should be made available to all parts of the country. I have to say with disappointment that since the inception of this scheme, only two institutions in Assam have so far been given this grant during these 12-13 years. This is my information, subject to correction. So I say there should be more attention paid to the backward and far-flung areas of our country.

About the reservation of ancient monuments and sites, there is one aspect that has to be mentioned. The beauty of the ancient monuments and sites is spoiled or destroyed by ugly construction in the vicinity. Perhaps the Ministry has no control over this. So, if necessary, they should amend the Act to prevent such unnecessary construction of ugly structures spoiling the beauty of the monuments and sites.

Then there should be facilities in universities to train up students in epigraphy, numismatics and iconography. I hope the Ministry will pay attention to this matter. I support the demand.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण और शिक्षा के बारे में मांग संख्या 24, 25 और 26 का मैं अनुमोदन करता हूं, हृदय से इसकी ताईद करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बातें मैं कहना चाहता हूं जो हो सकता है कड़वी हों, मीठी न हों, अनपैलेटेबल हों। कई मेरे साथियों ने कहा है कि कई मदें हैं जिनमें बहुत कम राशि रखी गई है। करीब 22 करोड़ लोग जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं उनके बच्चों को कुछ दिया जा सके, उसकी तरफ थोड़ा सा आपने ध्यान दिया है। पौष्टिक आहार, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आपने जो राशि दी उसको डेढ़ करोड़ से साढ़े चार करोड़ कर दिया है यह चिल्ड्रन चार्टर के मुताबिक है। 450 टाइम्स। चिल्ड्रन चार्ट्स के मुताबिक जो खर्च है उसके हिसाब में बताया गया है कि 1726 करोड़ है जो कि 4.6 प्रतिशत ही आता है। शिक्षा मंत्री महोदय ने छः अप्रैल को जब डिबेट चल रही थी क्या कहा था इसको अगर आप मुझे समय दें तो मैं पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"I think it would not be out of place for me to mention here that comparatively larger funds have been allocated for education in the proposed *Fifth Five Year Plan.*"

मुझे दुख है, तकलीफ है, खेद है कि विद्वान प्रोफेसर ने किस तरह समझ लिया कि ये जो रुपये हैं इसमें केन्द्र के अलग हिस्से हैं, राज्यों के अलग हैं, सब शामिल क्षेत्रों को अलग देने हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से टोटल आउटले में इसका परसेंटेज घटता जा रहा है। 7 परसेंट था पहली योजना में। घट कर हुआ 5.8 करीब पौने छः परसेंट दूसरी योजना में। तीसरी योजना में यह आया 6.9 यानी करीब 7 परसेंट। चौथी योजना में घट कर 5.2 हो गया और अब जो गरीबी से लड़ने और मुकाबला करने का उल्लेख प्लान के हर पन्ने में किया गया है, आप फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के पहले पार्ट के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की पहली पंक्ति को पढ़ें तो उस में इन्होंने कहा है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये ही मेरे मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य हैं और हमारे शिक्षा मंत्री बहुत सन्तुष्ट हैं कि ये लार्जर फंड्स दिए गए हैं। यह विद्वान सभा ही बता सकती है कि किस तरह

से लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ किया जाता है ? शिक्षा के किसी भी देश में इस तरह का खिलवाड़ चाहे वह शिक्षा का उद्देश्य हो या शिक्षा के सम्बन्ध में हो, नहीं किया जाता । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां ऐसी स्थिति है ।

हमारे यहां गरीबी है, ठीक है, हम बहुत गरीब हैं और 22 करोड़ गरीब लोगों के लिए का फी कुछ करने का उद्देश्य है । साढ़े चार सौ करोड़ आपने न्यूट्रीशन प्लान पर दिया है । डेढ़ करोड़ पहले देते थे । इसका मैंने पहले भी स्वागत किया और अब भी इसका स्वागत करता हूं । अब ये राज्य किस तरह से खर्च करते हैं इसकी तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं । आन्ध्र प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है कि 177.4 पर कैपिटा बजटेड एक्सपेंडीचर है एजूकेशन पर, यह 1972 की बात मैं बताता हूं और मैं एक ऐसे राज्य बिहार से आता हूं जिसकी गाथा कहते मुझे लज्जा आती है, सिर झुक जाता है । हमारी पर कैपिटा इनकम सारे देश में तीसरे नम्बर पर थी और अब वह 19 वें स्थान पर आ गई है । मैं अपना सिर झुका लेता हूं, हमारे यहां पर कैपिटा बजटेड एक्सपेंडीचर एजूकेशन पर 10 3 है—लोएस्ट इन दि वर्ल्ड, लोएस्ट इन दि कन्ट्री, परहैप्स लोएस्ट एमंग दि लोएस्ट है । यह हमारी हालत है । मैं इसलिये भावुक हो कर नहीं दुखी होकर कहता हूं कि हमारी गरीबी का यह भी एक कारण है कि उसकी तरफ ख्याल नहीं किया जाता ।

SHRI MANORANJAN HAZRA (Arambagh) Then why are you supporting these demands for grants?

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL Because you are opposing; because we are poor and we have every right to ask our Government to look to the most backward States. Please let me say something

हमारे मित्र का कहना बड़ा सही है लेकिन उनको पता नहीं है कि देश में कितना काम हो रहा है । सी० पी० एम० वाले तो एक तरह का तस्वीर खींचना चाहते हैं ।

कई लोगों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बदलना चाहिये । ठीक है । आप के० वी० एस० के नाम पर एक सस्था रखते हैं, केन्द्रीय विद्यालय संगठन । मैं दबी जबान से कहता हूं कि यह के०—केन्द्र के लिये है या किरानी विद्यालय के लिये है, आप किरानी देना चाहते हैं ? मैं शायद कुछ गलती कर गया, यह मैकाले विद्यालय की तरह है । सरकार ही अगर एक आदर्श नहीं रखेगी और शिक्षा को वोकेशनलाइजेशन की तरफ नहीं ले जायगी उसको कार्योन्मुख नहीं बनायेगी तो फिर हमारा भाग्य कौन ठीक करेगा ? दो दो विद्वान प्रोफेसर इसमें हैं और ये पैंडागागी जानते हैं, पैंडोगागी के बड़े विद्वान हैं फिर भी क्या होना चाहिये, किस तरह हम आगे चल सकेंगे, यह कुछ सामने नहीं आ पाता है । यह तो बिल्कुल ये जो दो प्रोफेसर हैं वे जानते हैं और नेता जी भी हैं वे तो खेल के नेता हैं मैं उन्हें भी दो-चार सुझाव देना चाहता हूं और दो चार बातें अगर मैं कहूं तो मैं समझता हूं—वे उसके ऊपर ध्यान देंगे । देश में केरल में काफी सिट्रेसी है वह हम लोगों के लिए एक लाइट है, हम लोगों का पथ प्रदर्शन करती है कि वे कम से कम खर्च करके शिक्षा का इतना प्रसार अपने यहां किये हुए हैं । वे 35.4 पर-कैपिटा इन्कम का खर्च करते हैं फिर भी वहां किस तरह से बच्चियां और बच्चे सब पढ़ते लिखते हैं । बिहार की बच्चियों को स्कूल जाने का बहुत कम मौका मिलता है और जब एनरोल किया जाता है तो उन्होंने फैक्ट्स एण्ड फीगर्स का एक छोटा सा महल रखा है । जिस तरह से सारे सागर को आप लोगों ने इस रिपोर्ट की गागर में भर दिया है मैं उसकी ताइद करता हूं और प्रशंसा करता हूं कि सारे देश की शिक्षा की एक साल में जितनी हुई उसको आपने उस रिपोर्ट में रख दिया है । उस रिपोर्ट को मैं गागर

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

कहता हूं । उस गगरी में क्या है उस को यही बता सकते हैं । एक चीज मैं बताऊं—

"All education is free in two States of the Union. The entire education is free in six States. Primary education is free in all States except three where it is so only upto certain classes or for some sections of students"

मेरा यह सब पढ़ने का मतलब यह है कि जो बिहार राज्य गरीब है, जो सब से नीचे है, जो तीसरे स्थान से गिरते-गिरते अब सब से आखिर में चला गया है, शायद मेघालय और दूसरा एक राज्य और उससे भी नीचे है क्योंकि वहा पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे राज्यों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

अभी हमारे आदरणीय मित्र विश्वनारायण शास्त्री जी ने संस्कृत की बात कही । वह देव-भाषा है, देव-वाणी है । सारे कल्चर की बात उससे उत्पन्न होती है । पंडित लोग बड़े विद्वान कहे गये हैं, मैं तो चाहूंगा कि इसकी रक्षा की की जाय । मगर आज आपने राष्ट्र भाषा और राज भाषा को भुला दिया है । आप हिन्दी के प्रति इतना प्रतिकूल ख्याल रखते है, आप कभी कहते हैं कि यह होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, कभी आप अपने जिम्मे लेते हैं । हमें पता नहीं लगता है आप इस राजभाषा को जनता की भाषा बनाएंगे या कौन सी भाषा बना कर रखेंगे ? मुझे बड़ी तकलीफ है और मैं कहना चाहता हू कि इस तरह से जो आपने पृष्ठ 11 में दिया है कि सारा देश इससे असन्तुष्ट है । इससे बढ़ कर असन्तोष शायद ही किसी विषय को लेकर देश में हो सके ।

. . . [illegible] के खेल राष्ट्रीय उपमंत्री [illegible] जी की बात देख रहा हूं कि किस तरह हम स्पोर्ट्स में, खेल-कूद में और शारीरिक शिक्षा में गिरते जा रहे हैं । हाकी में हमारा सब से ऊंचा स्थान, विश्व में सब से ऊंचा स्थान था । एशिया में हम सब से अच्छा काम कर रहे थे । यहां खेल होने को था । सारे विश्व के लोग आने वाले थे और क्या हुआ ? जाने नेता साहब और जानें ये मिनिस्टर लोग ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was discussed in the House.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : आप जानते हैं कि 1947 की 14 अगस्त की अर्द्ध रात्रि में हमारे महान नेता नेहरू ने क्या कहा था ? वह पढ़ कर मैं खत्म करूंगा । उन्होंने कहा था—

"भविष्य आराम से बैठने या दम लेने के लिए नहीं, बल्कि निरन्तर और भरसक मेहनत करने का है जिससे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकें जो कई बार हमने की हैं ।"

खासकर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के सैकंड पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में भी हम ने ये शब्द कहे हैं । उन्होंने आगे कहा है—

"भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों दीन दुखियों की सेवा है । इसका अर्थ गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की विषमता को समाप्त करना है ।"

मैं सरकार से कहूंगा कि यह विषमता क्यों ? कोई पब्लिक स्कूल में पढ़े, कोई वृक्ष के नीचे भी न पढ़ सके, ऐसी विषमता अब नहीं चलेगी । मगर आप ऐसी विषमता

करते हैं तो उस बड़े लीडर के, जो स्वर्ग में है, उसके खिलाफ काम करते हैं। प्रत्येक बात की आपको सोचना होगा। अगर आप नहीं सोच सके और उसको नहीं बचा सके तो आप मिट जायेंगे, ठहर नहीं सकेंगे। ऐसा करना हमारी शक्ति से परे हो सकता है पर जब तक आंसू हैं, दुख और पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिये हमें मेहनत करनी है, कठिन परिश्रम करना है ताकि हमारे सपने साकार हो सके।

इसलिये हमें स्व० नेहरू जी के इरादों पर चलना है ।

SHRI N. E. HORO (Khunti): Sir, I do not understand why the Education Ministry of a great country like India is not presided over by a Cabinet Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It was, just two years ago.

SHRI N. E. HORO: I take it that the Union Government is not giving much importance to this department. Otherwise, it would have been presided over by a Cabinet Minister. This department has been neglected badly. Everybody in the entire country is saying that our standard of education has gone down. There is much indiscipline in universities and colleges and in society itself.

Education should be a Central subject. I feel the entire educational systhem should be reoriented and vocational guidance should be an integral part of secondary education. Many people have said that education should be job-oriented. This universal demand should be looked into.

In university education, the University Grant Commission has been helping a lot through allotting funds, but I feel only a few privileged universities have benefited by this. There are many universities especially in eastern India, which have yet to get substantial grants from the UGC. In my area in Bihar, there are several colleges which are starving because they do not have sufficient funds. Those colleges are situated in areas populated largely by scheduled castes and scheduled tribes. Is it not the duty of the Education Ministry to look into it and see that UGC gives sufficient funds to the universities of that area? Some years ago there was a demand that Ranchi University should be converted into a central university. I do not know what has happened to it. But if the Government cannot agree to converting it into a central university, I want that a central university in Chotanagpur in Bihar should be started.

In several languages books are being published. There is National Book Trust. But I feel the Government have given only lip sympathy towards advancement of tribal languages. Why can't the Government take up this work? There should be more books produced by the Government in tribal languages. In eastern India where there is a large tribal population it is necessary that they should get education through the mother tongue I have been hearing that the Government is very sympathetic towards the condition of Adibasis, Scheduled Castes and Scheduled Tribes There is one aspect which the Government should take up immediately, namely producing literature in tribal languages This will go a long way in integrating the tribes of India and make them into good citizens.

Coming to adult education, I feel this has been neglected to a great extent. Adult education should be spread over the entire country. There should be a system by which all the villages are covered. The Union Government might say that this responsibility is with the State Governments. But if the Centre give proper direction and sufficient funds to the States to run this scheme, our country, which is still illiterate to a great extent, will have a large percentage of education

[Shri N. E. Horo]

in a few years. Since adult education and social education are the responsibilities of the Union Government, I would ask the Minister to consider this in right earnest.

In the field of social welfare, sports and cultural activities, I may point out that there was a time when India was at the top, specially in hockey. I want the Education Department to consider one point, namely, the opening of some regional commissions or committees. There should be a commission or committee for eastern India for developing sports and other cultural activities. There is much scope for it and you have funds. At the moment everything is centralised at one point and there is always struggle for power or office, like the one we have been hearing about the Indian Hockey Federation. If you decentralise this function and give sufficient funds to the different regions to organise themselves, they would give more emphasis to encouraging sportsmen and giving them training and in the days to come we will be one of the countries at the top in the field of sports.

If you look at the scheme of giving financial aid or stipends to the Scheduled Castes and Tribes, you would find that the amount was fixed years ago. Now the cost of living has gone up very much. The Government should reconsider this and give increased stipends, commensurate with the increase in the cost of living.

Very little has been done in the field of doing justice to the mentally retarded and crippled people. The Government should see that the different State Governments and also the voluntary agencies are geared up in order that millions of mentally retarded and crippled people could be looked after. I want the Union Government to consider these suggestions of mine in right earnest.

15 hrs.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के विचार सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है । मैं अपना अनुग्रह व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भी बोलने के लिए समय दिया । कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे सहयोगी श्री अरविन्द नेताम जी बोल चुके हैं, उन पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा और अन्त में हमारे शिक्षा मंत्री जी भी इस बहस को सम-अप करेंगे और पालिसी मैटर्स पर उनके विचार सदन में आयेंगे । लेकिन कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनसे मेरा सीधा सम्बन्ध है और उन पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा । खास कर यहां पर सेंट्रल स्कूल के सम्बन्ध में कहा गया है, हिन्दी के सम्बन्ध में कहा गया है, एडल्ट एजुकेशन के सम्बन्ध में कहा गया है और इसके अतिरिक्त स्टूडेन्ट प्रोब्लेम पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा ।

सब से पहले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकलापों के ऊपर जो संतोष माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रकट किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । कम से कम यह एक ऐसा संगठन है जिसका सदन के सारे सदस्यों ने सराहा है और यह मांग की है कि देश के देहाती क्षेत्रों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जायें । हमारे साधन सीमित हैं इसलिए हम वादा नहीं कर सकते हैं कि हम देहाती क्षेत्रों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोल सकेंगे । केन्द्रीय विद्यालयों का जो उद्देश्य था वह यह था कि भारत सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारीगण जो प्राय. ट्रांसफर पर जाया करते हैं, उन के बच्चों की शिक्षा का क्या होगा. उनकी समान शिक्षा के लिए एक माध्यम ढूंढा जाये अतः हमने इस संगठन का निर्माण 12 साल पहले किया था । इसमें खास कर सेना के लोग, जो हमारे और राष्ट्र के प्रहरी हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके बच्चों के लिए इस पर ज्यादा जोर दिया गया और आज देश में करीब 180 केन्द्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) . किसान खाना न दे तो वहीं मर जायेंगे वे लोग ।

श्री डी० पी यादव : किसान को भी खाना देना पड़ेगा अपनी सेना को और सेना को भी अपने किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी । यह तो रेसिप्रोकल है और इसी सम्बन्ध को बनाने के लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं ।

श्री विभूति मिश्र : केन्द्रीय विद्यालय गांवों में खोलिए ।

श्री डी० पी यादव : हाल्दर जी ने जो यहां पर कहा, मैं समझता हूं उनके मन मे कुछ भ्रान्ति हो गई है कि कौस्ट रेशियो कुछ ज्यादा है । नान-रेकरिंग पैसा जो खर्च होता है, नये नये विद्यालय बनाने के लिए, उस पैसे को भी जोड़ कर वे कहते हैं कि एक लड़के पर 600 रुपए खर्चा होता है । ऐसी बात नहीं है कि एक लडके पर 600 रुपए खर्चा होता है । जहां तक मेरा अपना कैल्कुलेशन है एक बच्चे पर रेकरिंग कौस्ट 410 रुपया सालाना जरूर आती है । लेकिन यह क्यों आती है इसके भीतर हमको जाना होगा और देखना होगा क्योंकि ऐसी ऐसी जगहो पर केन्द्रीय विद्यालयो की स्थापना की गई है जो बहुत हार्ड स्टेशन्स हैं जहां पर लड़के बहुत कम हैं । लेकिन जहां पर हमारी सेना का डिपो हो या इस्टैब्लिशमेंट हो वहां पर विद्यालय देना पड़ेगा । ऐसी स्थिति मे हमको हार्ड स्टेशन्स के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने पड़े हैं और हम अपनी सेना के लिए जो हमारी रक्षा करती है, उसकी सुख सुविधा के लिए, उनके बच्चों के लिए हार्ड स्टेशन्स पर अधिक से अधिक सेन्ट्रल स्कूल खोलेंगे ।

जहां तक विभूति मिश्र जी का सवाल है और हमारे जगन्नाथ मिश्र जी ने भी कहा है कि देहाती क्षेत्रों में स्कूल खोलने चाहिएं सो हमारे शिक्षा मन्त्री, प्रो० नूरुल हसन जी ने इस बात को कहा है कि हम ऐसे काम्प्रिहेंसिव स्कूल की स्थापना करना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारी आर्थिक मदद करने में हमको सहायता पहुंचाये और ऐसे कांम्प्रि-हेंसिव स्कूल की योजना हमने बनाई है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : किस क्षेत्र में खोलना चाहते हैं यह स्पष्ट कर दीजिए ।

श्री डी० पी यादव : ऐसी काम्प्रिहेंसिव शिक्षा की हमारी योजना है और माननीय सदस्यो ने जो असन्तोष प्रकट किया है और कहा है कि कांम्प्रिहेंसिव स्कूल आप खोलें तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में माननीय मदस्यों की इच्छा का भी ध्यान रखा जाए । आपने जो हमारी मदद की है डिबेट मे कि इसके लिए पैसे का आवटन हो, इसके लिए हम प्लानिंग कमिशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जायेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई : प्लानिंग कमिशन तो आपकी बात सुनता नहीं है ।

श्री डी० पी यादव : जाना तो पड़ेगा ।

प्रपोर्शन के बारे में मैं कह चुका हू कि 1-21 का प्रपोर्शन जो कहा गया उसमें हार्ड स्टेशन्स के लडकों की संख्या भी आ गई है लेकिन शहरो मे जो केन्द्रीय विद्यालय हैं वहां पर 1-35 या 1-40 का रेशियो है जो इण्डियन एवरेज के आस पास ही आता है । मैं श्री विभूति मिश्र, श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री हाल्दर जी को यह जरूर आश्वासन देना चाहूगा कि राष्ट्र की शिक्षा का किस प्रकार से माडल स्वरूप बनाया जाये इसके लिए केन्द्रीय विद्यालय समठन कोशिश कर रहा है । इस बात का आश्वासन मैं आपको दे सकता हू ।

[श्री डी० पी० यादव]

कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि केन्द्रीय विद्यालयों में अच्छे, उच्च वर्ग के जाते हैं, उच्चपदस्थ लोगों के ही जाते हैं। (व्यवधान) केन्द्रीय विद्यालय में एडमीशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सारे देश में जो विद्यार्थियों की परीक्षा सेन्ट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड से होती है उसमें आज केन्द्रीय विद्यालय का स्थान बहुत ऊंचा आ गया है और बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स जिनके बारे में लोग बहुत चिन्तित हैं उन पब्लिक स्कूल से केन्द्रीय विद्यालय का स्तर ऊंचा हो गया है और अब उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे है। अतः इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं हैं और यह आवश्यकता नहीं है कि पब्लिक स्कूलों को तोड़ दिया जाये या उनको हटा दिया जाये। केन्द्रीय विद्यालय आपके हैं, सरकार उनको चलाती है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, क्लास फोर, भी, सभी के बच्चो के एडमीशन होते हैं। यदि एक भी एडमीशन हमको कोई बता दे जिसमे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो उसमें सख्त कार्यवाही की जायेगी इस बात का आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : जो सरकारी आदमी है उनके बाल-बच्चो को उसमें लिया जाता है लेकिन वहीं के नागरिको के लड़के जो अधिक तेज रहते है, पढ़ने-लिखने मे होशियार भी रहते है उनको न लेकर प्रिफेन्स सरकारी नौकरो के लड़को को ही दिया जाता है तो क्या आप इस बात की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो मेरिटो रियल लड़के हों उनको केन्द्रीय विद्यालयो में ले लिया जाये ?

श्री डी० पी० यादव : दामोदर पांडे जी ने जो शंका प्रकट की है उसके सम्बन्ध मे मैं मैं पहले ही निवेदन किया है कि प्राइमेरिली यह विद्यालय केन्द्रीय सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं लेकिन जहां जहां स्थान खाली हुआ है हमने मेरिट पर एडमीशन किया है और करेंगे भी।

स्टूडेन्ट प्रोब्लम को लेकर बहुत सारे सदस्यो ने यहां पर गम्भीरता से अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस पर विस्तार से तो हमारे शिक्षा मन्त्री जी कहेंगे लेकिन विभूति मिश्र जी ने बिहार को लेकर एक सवाल उठाया था और सत्येन्द्र नारायण सिन्हा जी ने भी कहा था कि बिहार के छात्रों को आप बुलायें, शिक्षको को बुलायें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 18-19 तारीख से जो घटनायें वहा घटी है वह खेद जनक घटनायें हैं, उसके लिए मैं भी बिहार गया था और छात्र संघ के बहुत सारे लोगों से मिला शिक्षक संघ से मिला, सभी लोगो से मैं ने बातचीत की और वहा मैंने यह ऐलान भी किया था कि आप अगर यह अनुभव करें कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में कोई स्टूडेंट सेल खोलने की आवश्यकता पड़े तो हम उसमे आपका सहयोग चाहेंगे, उस बात को मैं यहां फिर दोहराता हू कि आप इसमे अगुवानी कीजिए और विद्यार्थियो के लिए जो भी सुख सुविधा केन्द्र या राज्य सरकारें दे सकती है वह देंगी। इसमे कोई भी हम को आपत्ति नहीं होगी। और आप ही नहीं मिश्र जी बल्कि मैं तो सभी अपोजीशन के माननीय, सदस्यो से कहूंगा कि विद्यार्थियो के जो मौलिक प्रश्न है, उन के खाने पीने का, रहने का, उन के कागज आदि के जितने भी प्रश्न हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर शान्ति से बैठे तो उन को सौर्ट आउट कर सकते हैं। विरोधी दलों के माननीय सदस्यो से निवेदन करूंगा कि यह जो स्थिति है उस का दुरुपयोग न करे, विद्यार्थियो को इस प्रकार से गुमराह भी नहीं करना चाहिये हम लोगो को। मैं आप को भी इनवाइट करता हूं, मैं आप के साथ काम करने को तैयार हूं विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिये।

श्री समर गुह : छात्र परिषद् को पहले डिसोल्व कर दीजिये, और संस्थायें भी जो हैं उन को भी डिसोल्व कर दें। यह पहला कदम होना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव : छोड़ दीजिये अभी छात्र परिषद् की बात समर जी। मैं तो पूरे विद्यार्थी वर्ग की बात कह रहा हूं। छात्र, शिक्षक हम सबों साथ बैठा दें।

माननीय मधु लिमये जी, छात्रों और नौजवानों की बात प्राय: कहा करते हैं, वह इस समय सदन में नहीं हैं, मैं आप के जरिये उन को भी कहना चाहूंगा कि माननीय लिमये जी जो भी सुझाव हम को देते हैं उसका एक माडल कहीं तैयार करके अच्छा हो अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में बना लें, हम सारे इनपुट्स उन को देंगे समर बाबू इस को आप नोट कर लें। तो मुझ को भी सुविधा होगी काम करने में। जो स्टूडेंट्स प्रोबलम को सोल्व करने में सहायक हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिये हम उन्हें सहायता देंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि छात्रों को गलत तरीके से गुमराह करने की प्रवृत्ति त्यागनी होगी। आज हम पावर में हैं कल आप हो सकते हैं, इस की कोई बात नहीं है लेकिन छात्रों को गुमराह करना त्यागना होगा। जो उन की बेसिक नीडस है उस में कैसे सहायता पहुंचे इस बारे में हम आप का सहयोग चाहेंगे।

इस के बाद कुछ ऐसा वर्ग भी है जो कालेज या स्कूल ड्राप आउट्स उन तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के लिये अगर आप रिपोर्ट के पृष्ठ 73 को देखें तो आप पायेंगे कि हम ने सारे देश में अभी करीब 100 नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की है और अगली पंचवर्षिय योजना में पिछली बार भी कह चुका हूं सारे देश के हर एक जिले में नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना करेंगे। इस का एक ही उद्देश्य है कि कालेज और स्कूल ड्राप आउट्स, लिट्रेट्स और इल्लिट्रेट्स जो भी पोटेंशियल यूथ कोर्स हमारे देश में हैं, उस को राष्ट्र निर्माण में किए प्रकार लगावें। उस का एक समायोजन, उस का इंटेग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाने के लिये नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना की गई है। आवंटन कितना है यह इस में दिया गया है। साथ साथ यह भी है कि सिर्फ शिक्षा मन्त्रालय ही नहीं, अन्य मन्त्रालयों से कोआर्डिनेशन कर के एन० एस० एस० प्रोग्राम को चलायेंगे। और इस बार हम एक नेशनल सर्विस वोलेन्टीयर स्कीम भी चलाने जा रहे हैं, जिस पर मन्त्री महोदय प्रकाश डालेंगे। उस सारे प्रोग्राम को इंटेग्रेट कर के राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कितना अधिक काम कर सकेंगे इस का हम को चिन्तन करना होगा।

हम एक नया प्रोग्राम और उठाने जा रहे हैं और वह यह है कि आज देश में 80 लाख ऐसे लोग हैं जो आंखों के रोग से पीड़ित है, हजारों चेचक की बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति नेत्रहीन हो इस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अत: इस बार हमारा मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय के साथ मिल कर राष्ट्र के बहुत से युवकों को यूथ अगेन्स्ट डिजीज प्रोग्राम के अन्तर्गत लायेगा। इस के लिये पैसे तो सब को नहीं दे सकते, यह सम्भव भी नहीं है। लेकिन सीड मनी की जो आवश्यकता है उस में करीब 20 लाख का आवंटन हुआ है और खास कर में बंगाल बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के शासनों का आव्हान करता हूं कि एक बीमारी चेचक है उस को ही इरेडीकेट कर दें तो बहुत बड़ा कल्याण हम देश का करेंगे। छात्रों की, नवयुवकों की शक्ति का सदुपयोग किया जाय इस में हम आप का सहयोग चाहते हैं। राष्ट्र का निर्माण हो, सारी बीमारियों का उन्मूलन हो, इसलिये यूथ अगेन्स्ट डिजीज प्रोग्राम सारे देश में चालू किया है। इस प्रकार जो डिवेलपमेंटल

[श्री डी० पी० यादव]

डिवीजेज सात आठ देश में हैं उन को समाप्त किया जाय इस के लिये ठोस कार्यक्रम चलाना होगा, ठण्डे दिल से।

जहां तक हिन्दी के प्रोग्राम की बात है। तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अपनी रिपोर्ट के पेज 75 से ले कर 90 तक की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस में जो आवंटन राशि है उस का विवेचन करने से कोई फायदा नही है। लेकिन मुझे खुशी है कि नान-हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में हम ने पिछले साल जो शिक्षकों की बहाली की है हिन्दी पढ़ाने के लिये उस मे 22,000 शिक्षक नियुक्त कर चुके हैं पुनः आगे आने वाले पांच साल के अन्दर 22,000 तो कंटीन्यू रहेंगे ही 10,000 हिन्दी शिक्षक और बढ़ाने जा रहे हैं। और मैं समझता हू यह एक मैसिव प्रोग्राम है जिस मे आप को सहयोग देना चाहिये। आप को जानकर खुशी होगी कि हम ने हिन्दी के विकास के लिये कोई भी कसर नही उठा रखी है।

अन्य भाषाओं का जहा तक सवाल है, संस्कृत का सवाल माननीय डी० सी० गोस्वामी, माननीय शिवनाथ सिंह, माननीय दीक्षित और शिव कुमार शास्त्री जी ने उठाया है माननीय बी० एन० शास्त्री भी संस्कृत पर बोल रहे थे, मैं उन से कहना चाहूगा कि संस्कृत के विकास का जहा तक सवाल है, आकड़े से जरूर पता चल जायेगा कि द्वितीय योजना मे संस्कृत के विकास के लिये हम ने सिर्फ 5 लाख रु० रखा था। तृतीय योजना मे 75 लाख रु० था जो चौथी योजना मे 2.75 करोड़ रु० हो गया और पांचवे पंचवर्षीय योजना मे संस्कृत के विकास के लिये हम ने 5 करोड़ 20 लाख रु० की राशि रखी है।

15 17 hrs

[SHRI NAWAL KISHORE SENHA *in the Chair*]

माननीय बी० एन० शास्त्री ने सेन्ट्रल संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का सवाल उठाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगले पांच साल में हम एक सेंट्रल संस्कृत रेफरेंस लाइब्रेरी किसी न किसी विद्यापिठ में खोलेंगे, उस की जांच पड़ताल हो रही है और हम आशा करते हैं कि मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी अगले पांच साल में अच्छे रूप में किसी न किसी विद्यापीठ मे हम खोल देंगे।

माननीय डी० सी० गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया था कि बिजाली प्रमतिशील असोसिएशन आसाम मे है उस को पैसे की कमी हुई है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिये उन्होने पैसा मागा था जो हम ने कम दिया। ऐसी बात नही है मैं ने कागज देखे उन्होने जितने शिक्षक मागे थे उतने शिक्षक हम ने दे दिये और आसाम के कोटे मे जो हिन्दी शिक्षक हैं वह भी आसाम सरकार ने जितना मागा था वह प्रायः हम ने दिया है।

रह गई बात अरेबिक उर्दू अदर इण्डियन लैंगुएजेज की। इन सारी भाषा के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना मे हम ने 10 करोड रु० रखा हैं और जो प्रथम साल खर्च होना होगा वह होगा लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिये मैं कहना चाहता हू कि पैसे की कोई कमी नही होगी।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : अभी बताया है मंत्री जी ने भाषाओं के विकास के लिए तथा अन्य कामो के लिए मैं पैसे का अभाव नही होने दूगा। यह खुशी की बात है और इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। इसी सदर्भ मे मैं उनका ध्यान बिहार मे स्थापित यूनिवर्सिटियो की ओर ले जाना चाहता हू। इस क्रम पे मैं मिथिला यूनिवर्सिटि का नाम लूगा। वहा पर हर काम व्यापकता से चल रहा है। लेकिन यू जी सी उसको ग्रांट नही दे रही है? मैं आग्रह करूगा कि बार बार उस यूनिवर्सिटी द्वारा और हम लोगों के द्वारा

श्री मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस पृष्ठभूमि में क्या आप उस यूनिवर्सिटी को उचित तथा यथेष्ट धनराशि देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री डी० पी० यादव : इसका जवाब शिक्षा मंत्री देंगे। उन्होंने इस को नोट कर लिया है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) इसका कई मर्तबा जवाब दिया जा चुका है। बार बार वही बात क्यों कहलवाते हैं ?

श्री जगन्नाथ मिश्र : वह नकारात्मक जवाब है। इस वास्ते बार बार कहना होगा जब तक आप कृपा करके उस यूनिवर्सिटी को धनराशि नहीं देते आप से अपील करनी होगी कि उस यूनिवर्सिटी को धनराशि देने के मामले पर आप गम्भीरतापूर्वक और सहृदयता पूर्वक विचार करें।

श्री डी० पी० यादव : हालदर जी और सुधाकर पांडेय जी ने एडल्ट एजकेशन पर गहरी चोट की है और कहा है कि हम उस में फेल हो गए है। मै मानता हू कि एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र मे जितनी प्रगति होनी चाहिये थी, नही हुई है। मै इसको खुद मानता हु कि हम उतनी प्रगति नही कर पाए है। लेकिन एक बात जरूर है कि यह विषय राज्य का विषय है, शिक्षा का विषय राज्य का विषय है और हमने कोशिश की है कि राज्य सरकारो से आने वाली जो स्कीमे है उन मे एडल्ट एजकेशन की बाबत भी, उसके लिए भी पैसा दिया जाए और पैसा दिया गया है।

बम्बई फंक्शनल लिट्रेसी के बारे मे एक प्रश्न शायद गौस्वामी जी ने उठाया है कि उसको ज्यादा पैसा दिया गया। मैं आपको कहना चाहता हू कि आप वालंटरी संस्थाएँ कायम करें, पैसे की कमी आपको नहीं होने दी जाएगी, एडल्ट एजुकेशन में पैसे की कमी आपको हम नहीं होने देंगे। जिस संस्था के संचालक आप होंगे अगर उसका पैसा कोई खा जाए तो मैं क्या करूं लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हु कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के सुसचालन के लिए पैसे की कोई कमी नही आने दी जाएगी। तेजी से और मजबूती से हम को काम करना होगा। इस मे आप सब के सहयोग की आवश्यकता है। जब तक यह प्राप्त नही होता है तब तक एडल्ट एजुकेशन मे सफलीभूत हम नही हो सकते हैं।

फक्शनल लिट्रेसी प्रोग्राम का जहा तक सम्बन्ध है 106 जिलो को हमने इस मे लिया है और कुछ और जिले इस मे लिए जाएंगे। नेहरू युवक केन्द्र के माध्यम से और एन एस एस के माध्यम से तथा दूसरी वालेंट्री एसोसिएशन के माध्यम से जब तक आप सारे काम को कोआर्डिनेट नही करेंगे तब तक फक्शनल लिट्रेसी का प्रोग्राम सकसैसफुल नही हो सकता है। सरकार आपको सीड मनी जरूर . .

सभापति महोदय क्या आप का ध्यान इस सुझाव की ओर गया है जो कई माननीय सदस्यो ने दिया है और समाचारपत्रो मे भी आया है कि हम बेकार नौजवानो को काम देने का प्रयत्न कर रहे है, तो एडल्ट लिट्रेसी सेटर खोल कर पचायतो के द्वारा हम इसको दे सकते हैं ? यदि इधर आपका ध्यान गया है तो उसके सम्बन्ध मे भी आप क्या कुछ कह सकते हैं ?

श्री डी० पी० यादव आप खुद इस मे इटरेस्ट लेते है। पिछली बार जब बिहार मे कुछ किसान आए थे उस समय भी आपने इसकी जिज्ञासा प्रकट की थी और बडी कृपा करके कहा था कि आपका जो बैंक है बिहार मे, कोआपरेटिव बैंक उसके आप चेयरमैन भी

[श्री डी० पी० यादव]

हैं और उसके भी पैसे का आवंटन करेंगे। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके पैसे का भी सदुपयोग हम करेंगे और प्रैक्टिकल पार्क्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। इस काम में मंत्रालय आपको सहयोग देगा और साथ ही आपका सहयोग भी चाहेगा।

कोऑपरेटिव्ज और पंचायतों के माध्यम से एक मसिव प्रोग्राम लांच करने की आवश्यकता है एडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए।

शिक्षकों की इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में श्री विभूति मिश्र ने सवाल उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि 25 लाख शिक्षक हमारे देश में है। अब 25 लाख को एन सी ई आर टी या इसके चार रिजनल कालेजों में ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। उनके कुछ लीडरों को ही हम ट्रेन कर सकते हैं। उनके जरिये इसका प्रोपेगेशन हो सकता है। पिछले साल मैंने इसका जिक्र किया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सारे देश की प्राइमरी स्कूल टीचर्ज ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि हमारे यहां आए और दस दिन तक उनका प्रशिक्षण हुआ। एन सी ई आर टी में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। हमारे भी उच्च धिकारियों और प्रोफेसरों को पता चला कि धरातल पर क्या स्थिति है और उस स्थिति को देखते हुए किस प्रकार का करीकुलम बनाया जाना चाहिये। इसका चिन्तन हम करेंगे। हर एक राज्य से हम लोगों ने कहा है कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुला बुला करके उस राज्य की क्या समस्यायें हैं उनको देखते हुए एक माडल स्कीम तैयार की जाए और उसको हम करेंगे। यूनिसेफ भी इसके अन्दर कुछ शिक्षकों की मदद करना चाहता है। राज्य शिक्षा संस्थान और राज्यों में जो टीचर्ज कालेज हैं उनकी भी हम काफी मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो 100 टीचर्ज कालेजों को और 400 टीचर्ज ट्रेनिंग स्कूल्ज को यूनिसेफ के अन्दर कवर करेंगे। इस तरह से टीचर्ज ट्रेनिंग के प्रोग्राम को मैसिव रूप में हम लांच करने जा रहे हैं। इसलिये यह कर रहे हैं कि करीब 55 हजार सर्विस टीचर्ज को और कुछ साइंस टीचर्ज को भी हम इन-सर्विस ट्रेनिंग देना चाहते हैं।

आपने पिछले साल कहा था कि शिक्षकों को एन सी ई आर टी के माध्यम से आप एजुकेट करें। शिक्षक प्रतिनिधियों को हमने एजुकेट करना शुरू कर दिया है और एजुकेट करेंगे। लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होगी उनको वापिस जा कर रिफलैक्स एक्शन स्टेट में चलाना होगा। इस में आपके सहयोग की भी आवश्यकता है और साथ ही राज्यों के शिक्षा संस्थानों को भी मजबूत करना होगा उस में आप हमारी जो भी मदद चाहेंगे हम करने को तैयार रहेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): आप ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा शिक्षक ट्रेन हो सकते हैं और ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी शिक्षक ज्यादा अच्छे होंगे तो इसके विद्यार्थियों को भी फायदा होगा।

श्री डी० पी० यादव: देश में 26 लाख शिक्षक हैं। उनको चार रिजनल में या एक एन सी ई आर टी के हैडक्वार्टर में हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। आप उसको लीडरशिप अपने भी दे सकते हैं। लीडरशिप के लिए महाराष्ट्र से भी काफी शिक्षक आ रहे हैं। हर एक जिले में दो दो शिक्षक आ रहे हैं। यह लीडरशिप प्रोग्राम अच्छा है।

श्री दलीप सिंह (बाम्ह दिल्ली): शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि शिक्षा के अन्दर प्रगति बहुत कम हुई है। मेरी राय है कि प्रगति बहुत ज्यादा हुई है। वह जमाना मुझे याद है कि जब दिल्ली में हम पढ़ते थे तो सारी दिल्ली के देहातों के अन्दर एक ही स्कूल होता था जिस का नाम था

महरौली' हाई स्कूल। आज दिल्ली के देहातों के अन्दर हर गांव में या हर दो तीन गांव के बीच में एक हायर सैकेंडरी स्कूल है और सारी दिल्ली में तकरीबन साढ़े आठ सौ हायर सैकेंडरी स्कूल हैं। इस तरह से काफी तरक्की हुई है काफी प्रगति हुई है।

लेकिन शिक्षा को आपने दो भागों में बांटा हुआ है। एक वह भाग है जिस में धनी लोगों के बच्चे पैसे के जोर से शिक्षा खरीद करते हैं और एक वह भाग है जिन में गरीब आदमियों के बच्चे जो गांव के बच्चे हैं वे पढ़ते हैं। जो धनी लोगों के लड़के लड़कियां हैं वे कारों में बैठ कर स्कूल जाते हैं सीधे स्कूल के दरवाजे पर कार से उतरते हैं उनको सुबह का ब्रेक फास्ट या लंच जो कुछ भी होता है मिल जाता है और उनको इतनी अच्छी किस्म की शिक्षा दी जाती है कि क्लिंग क्लास उन में से पैदा होती है। भारत में 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जहां पर किसान रहता है मजदूर रहता है खेतीहर मजदूर रहता है और वहां स्कूलों की हालत यह है कि वहां टीचर तक नहीं होते हैं।

दिल्ली में हमारे गांवों के लोगों ने एक एक स्कूल के लिए बीस बीस, पच्चीस पच्चीस एकड़ जमीन दी, और वहां खूबसूरत बिल्डिंग्ज भी बनी। लेकिन आज हालत यह है कि कितने ही स्कूलों में मैथेमैटिक्स के टीचर नहीं हैं। क्या सरकार इस शिक्षा पद्धति के जरिये समाजवाद लाने की बात सोच रही है? मैं श्री यादव का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने किसी भी शोबे के लिए पैसे की कमी नहीं बताई है। लेकिन दिल्ली, जो हिन्दुस्तान की राजधानी है, स्कूलों में मैथमैटिक्स के टीचर न हों और साइंस पढ़ाने का इन्तजाम न हो, यह एक अफसोस की बात है। एप्लीकेशन हो चुके हैं, लेकिन टीचर न होने की वजह से स्टूडेंट्स मैथेमैटिक्स नहीं पढ़ सके हैं। इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन स्कूलों में मैथेमैटिक्स के टीचर नहीं हैं और साइंस पढ़ाने का इन्तजाम नहीं है, क्योंकि उनमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं।

आज हमारे देश में मुख्तलिफ नौकरियों के लिए-आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० और इस० डी० ए० वगैरह के लिये काम्पीटीशन होता है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो लड़के गांवों के स्कूलों में पढ़ते हैं, वे कैसे उन काम्पीटीशन्ज में कामयाब हो सकते हैं।

मिनिस्टर साहब ने बताया है कि देश भर में 180 केन्द्रीय महाविद्यालय खोले गये हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होता रहता है, उन के बच्चों की शिक्षा के लिए इन स्कूलों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ने गांवों में शिक्षा के लिए क्या इन्तजाम किया है? इलैक्शन के सिलसिले में मैं हाल ही में बुलन्दशहर गया था, जो दिल्ली से चालीस मील के फासले पर है। मैं ने देखा कि गांव में स्कूल में एक कमरा है, आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, और वहां बैठ कर बच्चे पढ़ रहे हैं। इस के मुकाबले में जिन स्कूलों में धनवानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां सब तरह की सहूलियतें मौजूद हैं, वहां टैक्स्टबुक्स दूसरी हैं और शिक्षा पद्धति भी दूसरी है।

एक बार जब मैं अपनी कास्टीट्यूएन्सी में गया, तो मुझे यह देख कर खुशी हुई कि एक हरिजन लड़का, जिस का बाप जुलाहे का काम करता है, आई० ए० एस० में सिलेक्ट हुआ। इसी तरह एक दूसरा लड़का भी आई० ए० एस० में सिलेक्ट हुआ, जिसका बाप जूती बनाने का काम करता है। इस लिए यह न समझा जाये कि गरीब आदमियों का दिमाग नहीं है। अगर उन के बच्चों को मुनासिब मौका दिया जाये, तो वे भी इन काम्पीटीशन्ज में कामयाब हो सकते हैं।

नई दिल्ली में जो पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, उन में गरीब आदमियों के बच्चे नहीं

[श्री अमीन सिंह]

आ सकते हैं। जब सिलेक्ट कमेटी में दिल्ली स्कूल एजूकेशन बिल पर बहस हो रही थी, तो मैं ने मैनेजमेंट के एक प्रतिनिधि से पूछा कि उन के स्कूलों में इतनी फ़ीस ली जाती है, क्या उन में गरीब आदमियों के बच्चे भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो कुछ रईसों से लेते हैं। मैं ने पिछली दफ़ा भी कहा था कि सारे मुल्क मे एक शिक्षा पद्धति हो और सब स्कूलों में एक सी किताबें पढ़ाई जायें, ताकि गांव के लड़के भी दूसरों का मुकाबला कर सके। लेकिन सरकार मौजूदा शिक्षा पद्धति को बदलना नही चाहती है। भारतवर्ष की 85 फीसदी आबादी गावों में रहती है। सरकार का उन लोगो के बच्चो का भी ख्याल करना चाहिए।

हम देखते है कि जब सात, आठ या दस साल का बच्चा तीसरी या चौथी जमात मे पढ़ता है, वह किताबों का गठ्ठे का बोझ लाद कर ले जाता है। समझ मे नही आता कि छोटे छोटे बच्चे इतनी किताबों को कैसे पढ़ सकते हैं। जो हम लोग पढ़ा करते थे, तो थोड़ी सी किताब हुआ करती थी और उस जमाने का पढ़ा-लिखा आदमी आज कल के ग्रैजुएट या हायर सेकण्डरी पास से कही बेहतर है। इस लिये मिनिस्टर साहब बच्चो का किताबो का बोझ घटाने की कोशिश करें।

दिल्ली स्कूल एजूकेशन बिल को इस लिए पास किया गया कि टीचर-वर्ग को प्रोटेक्शन मिले और स्कूलों के मेनेजमेंट धांधली न कर सके। आज मुझे अनएडिड स्कूल टीचर्स एसोसियशन के सैक्रेटरी, मिस्टर पी० भाषान, की एक चिट्ठी मिली है, जो मैं मिनिस्टर साहब को दे दूंगा। उस में कहा गया है कि श्री अब्दुल लतीफ़ मिडलाइन स्कूल, पूसा रोड मे परमानेंट टीचर थे; उस स्कूल के जो मैनेजर हैं, उन की बीबी उस की प्रिंसिपल है; श्री अब्दुल लतीफ़ स्कूल की वैस्ट-पटेल नगर ब्रांच मे काम करते थे; उन को कार भेज कर हैड आफिस मे बुलाया गया और एक कमरे में बन्द कर के, जिस के बाहर दस बारह आदमी खड़े कर दिये गये थे, उन का रेजिग्नेशन ले लिया गया। आज वह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है। उस ने पुलिस मे रिपोर्ट की और लेबर कोर्ट मे दरख्वास्त दी, लेकिन कोई एक्शन नही लिया गया है। अब उस ने डायरेक्टर आफ एजूकेशन के नाम दरख्वास्त दी है। उस के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। अगर इस तरह एक गरीब टीचर का इस्तीफा जबर्दस्ती से लिया जाता है और मैनेजमेंट की तरफ से उस को परेशान किया जाता है, तो फिर दिल्ली स्कूल एजूकेशन बिल को पास करने का फायदा क्या है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें।

मेरी कान्स्टीट्युएन्सी मे हरियाणा शक्ति हायर सकंडरी स्कूल, कआवला, मे बच्चों और टीचर्ज की तरफ से प्रिंसिपल के खिलाफ छ महीने तक हड़ताल रही, लेकिन सरकार उस स्कूल को टेक ओवर नही कर सकी। पता नहीं, बच्चों का एग्जामिनेशन भी हुआ है या नही। जब मैं ने देखा कि कोई सुनने वाला नही है, तो मैं ने उस की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया।

देहात के स्कूलों मे सीनियर पी० टी० आई० भी नही हैं। हम अपने नौजवानों की दिलचस्पी खेलों मे पैदा करना चाहते हैं और उन को अच्छे खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। इस बारे में डायरेक्ट्रेट आफ एजूकेशन मे 1972 और 1973 में इन्टरव्यू हुए और पैनल बनाया गया, लेकिन आज तक किसी को

एपाइंट नहीं किया गया है । इन स्कूलों में पी० टी० आई० मौजूद नहीं हैं, तो हमारे लड़के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे । मिनिस्टर साहब को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक आर्कियालोजी का ताल्लुक है, हमारे यहां कितनी ही एनशेंट और हिस्टारिकल बिल्डिंग्ज हैं । मेरा गांव अलाउद्दीन खिलजी के किले के अन्दर आबाद है, जिस को सिटी सीरी कहते हैं । वह किला अभी तक किसी न किसी शक्ल में कायम है । उस की दीवारें भी दिखाई देती हैं । पहले मैं देखता था कि उस की प्रोटेक्शन के लिए कोई चौकीदार होता था । उस के साथ साथ मखदूम शाह औलिया की दरगाह और दूसरी बिल्डिंग्ज के लिए भी चौकीदार होता था । लेकिन आज वहां कोई चौकीदार नजर नहीं आता है । लोग फोर्ट की जमीन पर नाजायज कब्जा करते चले आ रहे हैं और फोर्ट को खत्म किया जा रहा है । मिनिस्टर साहब को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी हिस्टारिकल बिल्डिंग्ज सेफ रहें और हमारी पुरानी यादगार कायम रह सके ।

जहां तक शिक्षा पद्धति का सवाल है आप उस पुराने जमाने को याद कीजिए, जब राजा के लड़के, कृष्ण, और गरीब ब्राह्मण का लड़का, सुदामा, दोनों एक-साथ बैठ कर पढ़ते थे । उन दोनों का एक ही गुरु था और एक ही शिक्षा थी । उन दोनों में इतना प्यार था कि जब बाद में कृष्ण राजा बने, तब भी उन की तरफ से सुदामा को बहुत इज्जत दी गई । जिन को हम भगवान मानते हैं, जिन को योगेश्वर कहा जाता है, वह भी एक गरीब ब्राह्मण के लड़के के साथ बैठ कर पढ़ते थे । लेकिन आज हम देखते हैं कि धनवानों के बच्चे गरीब आदमियों के बच्चों के करीब नहीं जाना चाहते हैं — उन को बदबू आती है । धनवानों के बच्चे, ब्लैक-मार्केटियर्ज के बच्चे, देश के बेईमानों के बच्चे, जिन लोगों ने ब्लैक कर के पैसा कमाया है, उन के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते, हैं जहां उन को धूप और हवा भी न लगे जैसे कागज की पुड़िया में से निकले हों । वही रंग गोरा गोरा सुबह से शाम तक नजर आए और हमारे गांव के बच्चे जो बाहर बैठते हैं उन्हें गर्मी में लू लगे, सर्दी के दिनों में ठण्डी हवाएं लगें और आंधी आ जाय तो सारी धूल मुंह पर और उन के सिर पर जम जाये, फिर वह आप को कुछ देंगे नहीं और वे आप के लिए मेहनत कर के अन्न पैदा करेंगे आप को अन्न देंगे । तो आप का मुंह उन की तरफ क्यों नहीं होता है ? आप वहां उन बच्चों को बैठने के लिए जगह दीजिए उन के स्कूलों में हर एक सबजेक्ट का टीचर दीजिए । आज जब दिल्ली के अन्दर यह हालत है और 40 मील दूर बुलन्दशहर की बात मैं न बताऊं तो और जगह की क्या हालत होगी ? बिहार, उड़ीसा की हालत आप देखें, बहुत पहले मैं उसे देख कर आया हूं फिर दिल्ली की जब यह हालत है तो उस से मुझे लगता है कि उन स्थानों की क्या हालत होगी ?

मेरा गांव शाहपुर जट है जो हौज खास के पास है । जब मैं पढ़ता था उस से पहले वहां एक प्राइमरी स्कूल था और आज भी वही प्राइमरी स्कूल चला आ रहा है । डायरेक्टर आफ एजूकेशन को मैंने चिट्ठी भी लिखी । वहां हौज खास में एक हायर सैकेंड्री स्कूल था जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे । अब वह भी वहां से उठ गया है और उन को डेढ़ डेढ़ दो दो मील दूर जाना पड़ता है । तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन से कह कर एक हायर सैकेंड्री स्कूल भी वहां खुलवा दीजिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Chairman, Sir, a democratic and progressive nation is known by the quality of education it maintains and by the attention it pays to and the moneys it provides for both the quality and quantity of education. If you consider, therefore, the Ministry of Education's Report with this measuring yard, you will find that the report is far from satisfactory. Not that, it has not done many good things, which this Report mentions. Of course, it has done some good things. But from the very beginning of our Indepedence education has not been given the right priority, one of the top-most priorities, and we find a chequered history of our Education Ministers being inside and outside the Cabinet. I should have thought that particularly in a developing democracy, Education Ministers all along would be members of the Cabinet, and not only members of the Cabinet, but members who would also influence the decisions of the Cabinet. Every single decision you take, no matter whether it is on economic or social or on other allied subjects, the Minister of Education and his considered judgement and opinion are bound to be influential. Therefore, my feeling is, this report talks about many things, but it does not convey them in the real sense in which it ought to. The sad fact is that it just cannot convey. This is one thing.

The second aspect, is the Ministry of Education is constantly suffering from paucity of funds. This problem of paucity of funds and resources is a perennial one. This can be seen from the Report itself. In the Report, there is mention of this fact. When the resources for the Fifth Five Year Plan were being assessed,—the report itself says on Page (1) of the Introductory Chapter—the proposals for educational development in the Fifth Five Year Plan were estimated to cost Rs. 3200 crores. Later on, they were scale down to Rs. 2200 crores. Ultimately, the amount decided was Rs. 1726 crores My friend, the Deputy Minister yesterday talked very enthusiastically and rightly so, about the fact that the social welfare budget has been increased by six times in the Fifth Five Year Plan. I wish his enthusiasm prevails over the next five years. But I am afraid, as we pass through the next months and years, there will be some economies and cuts and I think those economies and cuts will always be far education and social welfare as if these are things which can be taken up at the last minute. As a matter of fact, these things should have been done earlier.

Now, I would briefly mention certain points about the Report. I would draw the attention of the hon. Minister to certain things and I hope he will give reply to some of the points. On page (v) of the Introductory Chapter, the report refers to the proposal to establish a National People's University for non-formal higher education. But, the details of this proposal have not been spelt out. We would like to know something about this. On page 9 the Report tells about the 'Teachers Day' and about the funds collected for teachers aid, and about the National Awards to and honour of teachers. It is all good, if you give to the teachers a honoured place in the society and give them aid, especially to those teachers who are economically needy. But, Sir, what about the other freedom? A good number of them, particularly the teachers at the higher education level, are unable to express themselves freely, and some minent professors are unable to go abroad. I would draw the attention of the Minister to this particular problem and I hope he will give answer to this particular question. Does the Ministry of Education enable outstanding scholars of this country to go abroad and attend international conferences, without any hindrance from the Government?

On Page 13 of the Report, we find that in the Fifth Five Year Plan, an allocation of Rs. 210 crores has been

made to the University Grants Commission. This is a very small amount. Bodies like the UGC should get much more amount. The number of universities has increased from 41 to more than 100, if you take into account those institutions as well which are known as deemed Universities. Now, when you have more than 100 such Universities in this country, you have allotted only Rs. 210 crores, for a period of 5 years. This is a very small amount, for distribution, for all round educational development. Then, again, out of these funds allotted to UGC, my grievance is that a lion's share is spent on Central Universities like Jawaharlal Nehru University. I have nothing against these Universities. I would like to see that these Universities are and should be properly developed. But, the distribution is not fair.

MR. CHAIRMAN: Do you mean to say that UGC is only Delhi University Grants Commission?

SHRI P. G. MAVALANKAR: That is what is happening!

PROF. S. NURUL HASAN: Do I deal with the Chair's observations also in my reply?

MR. CHAIRMAN: If the Minister so wishes, he is free to do so.

SHRI P. G. MAVALANKAR: By all means spend more on certain universities, but don't neglect others universities.

Coming to the Indian Institute of Advanced Studies, Simla, from Press and other sources, I find it is not faring well. There are complaints about its functioning, particularly its Director. I am not completely informed about it. The Minister should tell us whether this institute is delivering the goods as expected.

I shall now come to some general aspects. The role of education in a developing democracy is pivotal. But in the country today, whether it is primary, secondary or higher education, the picture is dismal and disturbing. Educational places and university campuses have become by and large barren and waste lands. The teachers and students do not feel inspired and hopeful about the coming events. The students especially are not hopeful whether they would get a placement after graduation. Of course, all education is not for jobs but all education is at least to make the individuals competent and able to stand up against all ordeals in life and grapple with the life's problems. Even that type of training and education is not made available to our students. We are neglecting education to our peril and to the peril of posterity. The human factor in economic development is very important. Then why should education have such a small outlay from the whole plan? The Education Minister should persuade his colleagues, and particularly the Prime Minister, that not only he should be made a Cabinet Minister but his ministry should get larger funds.

The other day he announced happily the revised scales for university and college teachers. But he did not mention anything about the improvement in the scales of 700 teachers of Delhi University who are placed in the selection grade.

PROF. S. NURUL HASAN: I have said in that statement that this matter is under the consideration of UGC and Government will take a decision after UGC's views are available to Government.

SHRI P. G. MAVALANKAR: Moreover it is no use merely giving more pay. Security is also important. Particularly in colleges under private management, teachers have no security. Even if they do not do anything wrong and they confine themselves to educational matters, they are not sure of remaining in their posts. Some times teachers are compelled to resign

[Shri P. G. Mavalankar]

because they are not finding favour with the management. Government should look into this aspect.

The Minister should also look into the conditions of Directors of Physical Education and Librarians. As a Principal for many years in a college in Ahmedabad, I know these people are as much a part of the faculty as any other members who teach this or that subject. Without a good Librarian and a good Director of Physical Training and Education, how are you going to have an overall educational development on the campuses of universities or colleges?

Look at higher education. The report says, in 1960 there were 45 universities. The number rose to 101 in 1973. In 1960-61 there were 1,542 colleges. Today there are 4,158 colleges. The number of students has also naturally gone up tremendously. The student explosion in the colleges and universities is so great that unless you do something concretely in regard to satisfying the students and making them know that you are concerned for them, you care for them, the students are bound to go astray.

A number of hon. Members belonging to different parties have referred to the disturbing student unrest. Some have called it student movement and others student power or student disturbance. I am one of those teachers who believe that we need not necessarily take a very dismal view of the student disturbances. Though I am very much tempted to quote, I would content myself by merely referring to a well known American social critic. Noam Chomsky, who has written a very fine book called *For Reasons of State* in which there is a chapter entitled *"The Function of the University in a Time of Crisis"*. I broadly agree with this social critic of America that the student movement and the student aggressiveness money and attention to the problems good singn. But it only means that we have to spend more in terms of and the sharp challenges they fling at us are something which we must welcome. These are, indeed, some of the hopeful developments of the day. On the other hand, if the students are going to be docile and conservative, taking everything lightly then we would be facing a real problem and a disturbing situation. So, this student unrest is a good sign. But it only means that we have to spend more in terms of money and attention to the problems of the students in the various campuses.

I find that in Gujarat today, a number of universities and colleges are in turmoil. Though there are committees established to look into those problems, every day we see students come out in processions. What are their demands? They complaint that there is no drinking water facility, no sanitary services, no bathrooms, no adequate class rooms, not many good teachers, not well equipped libraries, not modern laboratories, no books or playgrounds worth the name. But over and above all this, and apart from looking into the complaints of the students, there should be regular dialogue between the teachers and the students, so that the students, feel that they get something out of college and university education. At present they do not have that feeling. Therefore, if education is to become purposive, meaningful and fruitful then all our energy, money and attention should be poured into this educational endeavour in such a way that students develop themselves into cultivated, cultured and considerate citizens and they become self-respecting, self-reliant, sensitive and sensible individuals.

SHRI A. S. KASTURE (Khamgaon): Mr Chairman, I rise to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Education and Social Welfare. In this connection, I wish to bring to the notice of the hon. Minister some problems for his consideratioin. The statistics show that 87 per cent of the students enrolled for getting elementary education. That means 13 per cent of the students are not enrolled at all. Who are these students and

what are the reasons for their non-enrolment? It is obvious that these students are from the Scheduled Castes and Tribes and, as such, they are the worst sufferers. The main reason is that they live in the interior areas. In order to bring these people on par with others some solution must be found and efforts must be made to see that these communities get elementary education. I would request the Government to provide special incentives to help the enrolment and retention of these students in schools, such as scholarships, free-ships, residential schools (Ashrams) for Scheduled Tribes with some percentage of seats reserved for Scheduled Castes of that area, free distribution of text-books and stationery, mid-day meals, uniforms and attendance scholarships and some special benefits for girls If these measures are implemented, I have no doubt the children of Scheduled Castes and Tribes will come on par with others and take an active part in the building up of our nation. As a matter of fact, there is a constitutional obligation for provision of universal elementary education for spreading mass literacy, which is a basic requirement for economic development, modernisation of the social structure and the effective functioning of democratic institutions. It is also a first step towards the provision of equality of opportunity to all citizens.

The next problem is about adult education. This is a very important problem. I am glad to know that measures are contemplated for organising a large-scale campaign of non-formal education for youth in age group of 15—25 years in the Fifth Plan. The measures are very necessary because most of the children who drop out or are withdrawn from schools prematurely, do so for economic reasons. In view of the present level of per capita income and the nature and pattern of utilisation of the labour force, especially in agriculture, it is unrealistic to expect that the problem of drop-out can be completely solved in the near furture. But in the meantime some essential steps should be taken on an urgent basis. There should be provision of part-time classes for children who have completed five years of the primary school and who intend to continue education but cannot do so on a full-time basis and literary classes for those who have never been at school or have dropped out after finishing Class I or Class II.

The next problem is about the scholarships at the secondary stage for talented students from rural areas The object of this scheme is to achieve greater equalisation of educational opportunities to the development of rural talent and thereby to promote national integration. During 1973-74, scholarships were distributed amongst States and Union Territories at the rate of 2 scholarships for eash Community Development Block The same number is proposed to be continued during the year 1974-75. This number is most inadequate and hence in order to give opportunity to more rural talents, the amount and rate should be at least 5 scholarships per Community Development Block out of which at least one is from Scheduled Castes and one is from Scheduled Tribes necessarily.

About the National Scholarships for study abroad, this scheme was instituted in 1971-72 and provides financial assistance to meritorious students who are citizens of India and who do not have the means to go abroad for further studies. These scholarships are available for post-graduate studies. The number of scholarships awarded under this scheme every year is 50. I do not know whether during the last 4 years some Scheduled Castes/Tribes students have been sent abroad under this scheme and, if not, I would request the Minister to reserve seats for Scheduled Castes/Tribes students every year for these foreign scholarships as these students have no means to go abroad.

[Shri A. S. Kasture]

Another point is about the Post-Matric scholarships. The rates of scholarships are old and there is a need now for revision of these rates as the cost of living index has gone up. This is the Government of India scheme of Post-Matric scholarships for the Scheduled Castes/Tribes students studying in colleges. They get Post-Matric scholarships at various rates faculty-wise. I think, the rates were fixed in 1950-51 under the Post-Matric Scholarship Scheme. Since then, the same rates are still continuing. In spite of the demand from various students unions and associations and also by the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, no attempt has been made to revise these rates. As matter of fact, these students, if they live in hostels, get a very paltry sum of Rs. 40/- and day scholars get only Rs 27/-. These are the rates which were fixed in 1950-51. In spite of the demand to revise the rates, the rates have not been revised. The cost of living index has gone up and, as such, the rates should have been raised. But so far it has not been done. I do not know when it will be done. It shows that the Government is not paying any attention towards the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There is another point regarding various Institutes of Technology. There was a Committee appointed under the Chairmanship of Mr. K. T. Chandy. They have submitted the report. I have got a copy of that report. The Committee was constituted by the Council of the Institutes of Technology on admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. They submitted the report on 6th February, 1973. The hon. Minister of Education noted that and approved it on 16th February, 1973 But in spite of that, their recommendations have not yet been implemented. There is a provision in this report that it will be brought into force from this year 1973-74. Some of the students studying in these Institutes have met me and explained their difficulties. In spite of the report being in their favour, they are not getting any advantage of the report. The recommendations of the report are as follows:

"All SC/ST candidates who have passed the Higher Secondary Examination or equivalent be admitted against the quota reserved for them on the basis of their performance in the Joint Entrance Examination. Their performance should, in no way, be related to the minimum standards prescribed for the general candidates for qualifying at the Joint Entrance Examination.

All SC/ST candidates be given free tuition, exemption of hostel seat rent and a scholarship of Rs. 150/- p m to cover board expenses and a food grant of Rs. 300/- per year."

16.00 hrs

Those students who are studying in the Institutes of Technology are not getting these facilities, and if immediate steps are not taken to provide them with these facilities, some of them may leave the institutions.

With these words, I support the Demands for Grants.

SHRI SAMAR GUHA: The grant for the Ministry of Education is so insignificant that I do not know whether I should say that I stand to support it or I stand to oppose it.

MR. CHAIRMAN: You may keep silent on that.

SHRI SAMAR GUHA: I will not make any observation on that. In 1973-74 it was Rs. 130 crores; in the revised estimates for 1973-74 it was slashed to Rs. 116 crores. Now for 1974-75, the provision is Rs. 113 crores only. So, I do not want to make any observation about that. Since Independence, if any department in our country has been neglected by the Central Goverament, it has been Education. I do not know whether the

Planning Minister and others think that hand, divested from mind, can work.

Now I would like to make a few observations I would, first, say some thing about Prof. S. N. Bose. I want to remind you that when late Pandit Jawaharlal Nehru visited America he met Prof. Einstein, and the first question that Prof. Einstein asked Panditji was, 'How is Prof. Bose?'. And Panditji did not know who it was, whether it was the political Bose or come other Bose. It was about Prof. S. N. Bose. I want to remind you that, if Prof. Einstein had lived a year more, Prof. Bose would have got the Noble Prize. It was Prof. Einstein himself who suggested his name for Noble Prize, but before he could formalise it, he died. I have written to you about the way Prof. Bose was treated by one of your Secretaries or Under Secretaries. In the form of a letter addressed to him, they had said that his application for National Professorship was under consideration. The close associates of Prof. Bose suppressed that letter lest it should be a rude shock. Yet, the news percolated. I would request the Minister to see that his officials have some sense as to whom they are dealing with. I know you have written a letter of apology; I have seen that Do such persons, who dare to write such a thing to an eminent student of science, deserve to be in any department of Education? It was a matter of great distress for all of us I have written to you, Sir. Many scientists who worked on his statistics have got the Noble Prize. But Prof. Bose was absolutely careless about himself; he never tried for it; he was not concerned with earthly affairs. Many names of Noble laureates may be forgotten, but the name of Prof. S. N. Bose will remain so long as fundamental physics, fundamental science, is there. I request you to take some measures to honour him. We have not accorded him any national honour—not just as a National Professor; it is nothing for him. You should take initiative to set up an institute dealing with fundamental science in his name—in the name of Prof. S. N. Bose. That is my first request.

Secondly, the room in which Prof. Bose was living for the last many years, its condition is not very good. You should take some steps for the preservation of that room.

Thirdly, there is a nucleus of scientists who are working on Bose's statistics and they will soon be requiring some assistance from you. Not much they will demand from you. Kindly see that you can accommodate them. They are the Bose Group of Scientists working in Calcutta. They will be sending you their note soon.

Another thing. Perhaps you know that. You had sanctioned a project of helium gas which is absolutely essential for atomic energy and for space work and that is a project submitted by Prof. Bose for his national professorship. Unfortunately, Prof. Bose is no more with us. In Birbhum and Bihar areas there is natural gas and there is an immense quantity of helium. In other countries it is not so. The Atomic Energy people said that they will have any amount of helium. You have sanctioned this project only upto August. Please have a dialogue immediately with the Ministries of Science and Technology and Atomic Energy so that the whole project could be taken up and developed further. That will not only obviate our necessity to import helium from outside but it will have a great export potential also which will earn us valuable foreign exchange. For that reason, I will request you to see that the helium production project that was being developed by Prof. Bose is quickly undertaken. Just a few months after his death there was a curious situation and the whole organization was going to collapse. Fortunately, you have extended it upto August. Naturally, after discussions with the other

[Shri Samar Guha]

Ministries, I hope you will extend the project.

You have announced increased scales of salaries for the University and College Teachers. Coming as I do from that fraternity, naturally I am very happy that they will be the most benefited by the quantum jump of increase in their salaries. I welcome it. Though I welcome it, at the same time. I will be happier still if you had taken an integrated view of the whole of the teaching community, not of the College and University teachers only. What is the number of University and College teachers? 1,39,000. Primary School teachers—17,22,000. Secondary and Higher Secondary Teachers—5,76,000. So, the school-teachers put together number 23,07,000. If I add to it the other employees in the schools, it may be 25 lakhs. You have given the benefit to the College and University Teachers. I have made a little calculation. 5.5 per cent of the teaching community will be benefited by your acceptance of the recommendations of the Third Pay Commission. Prof. Hasan, if you have done first with the primary teachers, then the secondary and higher secondary teachers and then the college and university teachers, I would have understood and appreciated it more. You know what the teachers are getting at the moment. Less than a Class IV official. I can give the figures You know it. What are you going to do about the recommendation with regard to primary teachers, the secondary and higher secondary teachers? Are you going to accept the recommendations of the Third Pay Commission? If you are not accepting them and if you say that it is a State matter, you cannot escape it. Prof. Hasan, you have given a clarion call to all primary teachers, to all secondary and higher secondary teachers. who together number about 25 lakhs and to more others and if they come on the streets, what will you say? If socialism has any meaning, they should have started from primary teachers. Then they should have gone to secondary teachers and higher secondary teachers and them to college and university teachers. Although I am a beneficiary by the announcement made by Prof. Hasan I would like to state that he will not escape this by just saying that the matter will be settled by the State Governments. Sir, you have given the clarion call. If you do not accept the Pay Commission's recommendations, if you don't convene a meeting of the State Education Ministers and find a way out, things will take a different shape in which thousands and lakhs of teachers will be involved

PROF. S. NURUL HASAN: Let it not be a threat.

SHRI SAMAR GUHA: It is not a threat. You have given a clarion call. You have acted as a leader. You have shown the way. It is all right about the higher echelons. But what about the bottom 95 per cent? That question is most relevant. It is a most explosive question.

You should have an integrated policy. Instead of that a mess is created regarding secondary and higher secondary education. You have given the scheme of school education; it will be in the next Fifth Plan, two plus two in school and 3 years in college education. Now so far as the course and syllabuses are concerned, so far as the syllabuses are concerned, method of teaching and examinations are concerned, these are all in a mess. In some States they are setting up junior colleges. I say, it will be a dangerous thing to set up junior colleges. The reason is this. The students have one psychology in the school stage; they have a different psychology in the college stage Different types of disciplines are involved in the school and college stages. You can easily deal with students in the school stage and develop their faculties and sense of discipline but it will be difficult in college stage because they will develop a kind of 'immatured maturity' in the junior college

stage. So this danger is there. And therefore I suggest that there should not be junior colleges. Please give up this idea altogether. You should have secondary two years, higher-secondary 2 years as in Delhi. You should be very firm about these things. There are some other issues connected with this but I will not go into them in detail due to lack of time.

I have nothing against Hindi because it is our national language but there are other national languages also. So far as non-Hindi speaking areas are concerned the three-language formula was accepted long ago, but what allotment have you made? There are about 11 to 12 items here. These are for non-Hindi speaking areas. There are items like post-matric scholarsips. teachers' appointment, Teachers' training, Hindi medium college, voluntary organisation, writing books in Hindi, correspondence course, Hindi Encyclopaedia, Hindi Propaganda abroad, post-matric studies Hindi Library and so on. What allotment have you made? A meagre Rs. 328 lakhs. About the expenditure for Hindi, I do not grduge it. But the point is this. You have not allotted even a single farthing to teach and develop that idea of three-language formula in the Hindi States. Do you think you will develop national integration by this way? If you do not have this three-language formula it is not easy for the rest of the non-Hindi areas to adapt themselves emotionally.

You have done a great wrong because you have not allocated a single farthing for teaching any additional language—teaching Tamil in U.P., teaching Telugu in Punjab or Malayalam somewhere also. You have allocated Rs. 8.32 lakhs for the development of Urdu.

MR. CHAIRMAN: This is wonderful idea. Please conclude now.

SHRI SAMAR GUHA: I shall take two minutes more. I want to draw his attention to one point. What is the kind of amount that has been provided for by the Education Ministry for propagating the ideals of Gandhiji; but for Netaji, what have they done? There is sheer discrminatory policy that is being followed by the Education Ministry. I do not want to use the word discrimination because I do not know whether it is correct or not to use that word. I have with me a catalogue of fifteen items or so. For one year only, in the year 1971-72, a sum of Rs. 156 crores has been spent. For propagating the ideals of Gandhi i, they spent Rs. 9.75 crores but, for Netaji, only Rs. 3 lakhs has been spent. And recently, they have set up a Sports Association in Patiala. They have added Rs. 10 lakhs for the purpose It is not very much. I know that the hon. Minister has got very much admiration for Netaji But, still, not much has been done. You should have allotted more funds for the purpose.

PROF. S. NURUL HASAN: I am very happy that I am being given a lecture on History by my distinguished friend, Shri Guha who is a scholar on Chemistry.

MR CHAIRMAN: He also talked about something in scientific terms a little while ago.

SHRI SAMAR GUHA: As a Professor, I can give an answer outside. Just at the moment you used the word lecture. In the University Campus the word lecture has a different connotation On the floor of Parliament at least you should have that much of understanding and decency by using the word lecture. you have lowered yourself you being a Professor yourself.

Anyway, I want to remind you about one thing. You might remember that in Delhi for the teachers of Thirtyfive Government-aided schools you promised some selection grades

[Shri Samar Guha]

when they demonstrated. On your assurance, they withdrew their agitation. That has not been fulfilled.

I hope you will keep that assurance in mind.

SHRI D. P. YADAV: I have already assured the House.

SHRI SAMAR GUHA: I have another very interesting thing from the Kharagpur IIT. I have talked also to the new chairman. He has found a tobacco company and from there he has suddenly got one gentleman, a personal adviser, on Rs. 1800; and another person has also been recruited. I know it and everybody knows it; that gentleman Mr. Haksar had two friends in certain tobacco companies and those two friends have been drafted there for specialisation in the IIT. You will be astonished to know that they called a meeting of the students in the Calcutta Club; it looks so progressive as if we are living in Sweden or Norway or Paris or some such place. and not soft cold drinks but hot drinks were served to the students by the director or the governors themselves. This matter should be looked into.

I do not want to have a dig at the hon. Minister. But if any Minister thinks that his *alma mater* is the repository of all genius, naturally certain suspicions would be roused. Recently, there had been innumerable recruitments from that *alma mater* of the hon. Minister which creates certain questions. I just leave it to him for making a little bit of heart-searching

MR. CHAIRMAN: I do not want to give any lecture to the hon. Member since he is objecting to it. But he is just not looking into my case at all.

SHRI SAMAR GUHA: I shall conclude in a minute.

As regards the NCERT, it is doing good work. At least for one particular book in chemistry at the school level I had occasion to have consultations there. But I feel that could have been done better because it can be done better. There are about a dozen professors, and recently Government have brought a good man as a director there and there are a hundred lecturers. But I would make one suggestion for the hon. Minister's serious consideration. These professors and teachers of the universities and colleges have their own specialisation in their specialised fields dealing with students of special categories, but they have no practical experience of dealing with and knowing the mind of the school students. Therefore, the hon. Minister will do well to prepare the model books by getting the help of at least a few school teachers of different categories having long-standing experience of ten or fifteen years. Only then the model will be a realistic thing and the expenditure that is being made will be commensurate with the output.

SHRI BANAMALI PATNAIK (Puri): I would not like to speak much about higher education, but about our educational system in general. Our educational system should be an instrument for making social change. It is our aim to establish a casteless and classless society. We have to see how far our traditional system of education or our National system of Education has suceeded in achieving this objective. Commissions after commissions have been appointed and all the big educationists were associated with them and they made their recommendations, but we do not know how far those recommendations have been considered and implemented. First, we had the Lakshmanaswami Mudaliar Commission, then we had the Dr. Radakrishnan Commission and then we have had the Commission headed by Dr. Kothari. All these commissions have made their reports, but we have failed to abide by their recommendations.

Still, we have not arrived at any decision in regard to the duration of the higher secondary course. First, we had the high school system, then we had the PUC, and again we are going back to the twelve-year school

education. Even in Orissa, there are three universities and each of them is following its own system. In one university they have PUC and in another they are having IA and BA, with the result that if a student who has studied in one university wants to go and join another university he is in great difficulty. Why should we not evolve a uniform pattern of education with uniform standards all over the country? The Central Advisory Board of Education should have been able to enforce a uniform standard all over the country, so that if a student from Orissa goes to Kerala he may be admitted in the same class in the same school or college. There must be some such standard system. But unfortunately that standard pattern is not there and everything differs from one university to another and one State to another. Unless we enforce a uniform standard, our idea of national integration would be put in great jeopardy. It is for the Education Minister to solve this question.

Of course, he may say that education is a State subject and the State Governments do not like it if anything is enforced by the Centre, and even the universities have got their own autonomy. But the inter-university board should have been able to enforce this. After all, there is some purpose in having this uniform standard, namely that our students should not be put in a helpless position.

There are Central universities also. Previously, a large number of students from other States used to go to Banaras or come to Delhi to study. Nowadays, of course, they are coming to Delhi but they are not going in such large numbers to Banaras as before. What is the trouble with the Banaras University? After all, that is also a Central university. Perhaps, it is because of the language formula that there is some difficulty. By all means let Hindi also be taught, but side by side, English should also be taught in the universities.

In Central Universities, there must be a certain quota reserved for students from other States also.

Recently, the Minister of Education made a statement about the scales of Pay for university teachers as recommended by the UGC. This is a good thing. But are all these things implemented? Even the previous scales of pay have not yet been implemented in many States. It is very difficult for the States to implement it.

Recently the Chairman of the UGC wrote to the Vice-Chancellor of Utkal University that University education in Orissa is of the lowest, that whereas the ratio is 7.5 all-India it is 2.5 in Orissa. How are you going to improve it? If you look at the State Government's plan, there is little provision for higher education. They cannot pay the increased salaries to university teachers, leave aside the question of other government college teachers. How are you going to rectify this regional imbalance?

MR. CHAIRMAN: You were a Minister of Education in your State. You could give some suggestions.

SHRI BANAMALI PATNAIK: Those days are gone. It is only a question of finance. Without finance, it is very difficult to implement these things. For example, in higher education, there is little provision in the plan. That being so, how can you think of establishing new colleges under the Fifth Plan? Where is the question of implementation of higher scales of pay for college teachers? The State Governments are in difficulties. Their finance is jeopardised. They cannot implement the Education Minister's programme of higher scales of pay.

Postgraduate teachers in Government colleges are not entitled to the UGC scales of pay. What is the difficulty? Only of finance. This is the same difficulty in your State. In Government colleges, the teachers do

[Shri Banamali Patnaik]

not get the same scales as the UGC has recommended. This is the position in most of the States.

There must be some uniformity in this matter. For this purpose, if there is exchange of teachers and there is an all-India service of all teachers in postgraduate colleges, it will improve matters. Then universities are functioning like isolated citadels. They do not exchange teachers. There should be an all India standard. Teachers from one university should be able to go to another university. They should have the same improved standard of scales for all. This will improve the teaching standard. I will not say more about higher education.

There is talk about vocationalising education. Sometime ago when Dr. Nagchowdhury was member of the Planning Commission in charge of Education, there was a committee to inquire into the vocational system of education under his chairmanship. They have submitted their report. Most of our students come from rural areas. The rural folk constitute more than 50 per cent of our population. They live on agriculture. They belong to the agricultural community. In the report, it was recommended that in higher secondary schools, agriculture should be one of the subjects taught and it should be vocationalised in such a way that when they go back to their villages they should be able to work as some semi-skilled workers with scietific knowledge about agriculture. This type of education will ensure that they will have this type of knowledge from the very baginning. But we have not taken steps in that direction. What has happened to that report? Dr. Nagchowdhury is now Scientific Adviser to the Defence Ministry and is shortly taking over as Vice-Chancellor of Jawaharlal Nehru University. He is an eminent educationist; there were agricultrists and men of eminence in the educational world in that Committee. But nothing has been done in implementation of their report under the Fifth Plan by way of vocationalising education so that agriculture receives first attention at the Secondary stage so that when these students go back to their villages, they can work as semi-skilled workers.

Coming to the development of tribal education, the standard of education there is low. What is the difficulty? They speak tribal dialects. They have no written language. We post teachers in such areas who do not know their language. For example, Koraput, which is adjacent to the area from which Shri Netam, the Deputy Minister, comes, many people speak the Koya language. The teachers who are sent there should know the Koya language. If you say 'Mango', they will not understand. You should use the Koya equivalent of it. Similarly in regard to the Soura, Gadva or Kond area. The teachers must know these languages. Their vocabulary is limited. There are 300 to 400 words which are in common use. These should be translated and put in their own script, in the Oriya script where they speak that language and in Telugu script those areas in Andhra Pradesh where they live or if it is in Madhya Pradesh, in the Hindi script These 300-400 words should be adopted into that language. All the teachers should be given a special type of training. They should be given a special allowance for the purpose so that they can teach people there and the students are attracted. If that is not done, then it becomes difficult. Therefore, in those tribal areas educational facilities are lacking and education is not progressing, and that is because the students are not attracted for the training of teachers. Moreover, it is very difficult to find out the teachers in that community who can teach them in that language. So, it should be the endeavour on the part of the Education Ministry to have a special programme, some sort of package programme at the level of the Centre. It should be a Central programme so that the people in the backward areas and the tribal areas get primary education, gradually get more

educated and teachers are recruited for that purpose, and so that they get some sort of allowance to teach these languages. Moreover, in the other areas, either in the Zila Parishads or in the Panchayat Samitis there are some houses, but in the tribal areas there is nobody to build houses. Therefore, most of the schools are eo-educated under the trees. There is no class-room for those people. The teacher has no House because the tribal people have no house. So, it is vrey difficult for them to have a school-building. What can the teachers do and where can they stay? This is the problem. So, under the minimum needs programme, we should lay emphasis on this point in respect of those areas and we should improve those areas which are socially and educationally backward and see that they get better education and the standards of the students are improved.

I must congratulate the Minister for declaring the Jagannath Temple as an ancient monument of national importance, and for taking over the management of that temple. I think the declaration, however, has not yet been made and that process is there. It is one of the temples of national importance. It is, however, in decay. It is leaking. Rain-water is leaking and flowing through the temple. So, it is very difficult, and if early steps are not taken to repair the temple, this ancient temple will go to ruin.

Sir, Orissa is full of archaeological monuments. The other day, while I was speaking, I mentioned about the Pushpagiri university which was under excavation. The excavation report is not yet out. Miss Debala Mitra had conducted a tour of research and excavation but nothing has happened about them; the reports have not come out. It is a very important work which she was conducting. The entire eastern region, beginning from Puspagiri to the end of the Rishikul river is full of ancient monuments; most of them are in decay. Nothing has been done so far for its protection. Of course, the Minister will say that it is due to lack of funds and so we cannot create more circles. I think in the eastern circle, most of the ancient monuments lie in Orissa. So, Orissa needs a separate archaelogical circle. Unless that is created there, most of ancient monuments will be decaying and the properties will be stolen

Allegations have been made about the Superintendent of the Konarak Museum with whose connivance many beautiful deties are being taken away by the tourists. So far, however, no steps have been taken. Every day, in spite of our Act, the Antiquities and Art Treasures Act, most beautiful ancient antiques are being stolen and taken away by the foreigner. What step are you going to take to prevent this? Unless we strengthen the Archaeological Department, unless we appoint more care-takers and unless we appoint more people, it is very difficult to protect them. Of course, the State Governments can do it. It has to be done with the collaboration of the State Governments.

The other day I mentioned about the 64 Yogini statue which is a rare piece of its kind. The entire region in the east is reminiscent of the ancient Buddhist culture and the blending, and the tantric culture along with the Brahminical culture. All these temples are a blend, a mixture, of the Brahminical culture. All these ture. What has happened to these temples now? They are not protected.

Recently, when the Salandi project was in progress, in that village, the Atalokiteswara Buddha a prominent, standing statue of the Buddha, and a large number of Buddhist images were found. The word Baidakhya comes from Buddha. Nothing has been protected. We wrote to the Archaeological Department, but no steps have been taken. Similarly, there is the beautiful temple of

[Shri Banamali Patnaik]

Khetching in the district of Mayurbhanj which is next to Konarak. That is not yet fully protected. What steps have been taken by the Archaeological Department in this direction? They generally go and see the site and come back. Of course, there is lack of funds. But there must be proper co-ordination with the State Government and the Archaeological Department of the Government of India so that all the ancient monuments are preserved well and can stand the test of time.

There have been proposals for locating the regional sports centre in Orissa. I have been suggesting to the Minister to locate it in Cuttack at the Barabati stadium which is one of the best of its kind in Orissa. What has happened to the proposals? It is, I think, much better than the Calcutta stadium. Anybody who sees it can be proud of that stadium. If we locate the regional sports centre there, we can coach the students by giving all the facilities there, so that we can achieve our goal, because we are very much lagging behind in the field of sports. There are not sufficient facilities and sufficient attention is not paid to the coaching aspect, and so in the international field we do not have such a name as we ought to have. It is necessary that we should develop our regional sports centres to see that proper coaching is given to the students and we achieve a good name outside India.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Roza Deshpande.

Before you begin, I have to announce—it always falls to my lot—that the time is very short. There is hardly 30 minutes left now and there are six speakers. I would request the hon. Members to plan their speeches in such a manner that they complete it in 5-6 minutes. I would not be able to give more than that.

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (Bombay Central): Sir, I would like to emphasise one point that this Ministry is connected with a very sensitive, rather volcanic section of our society, namely, students and youth. I would like to point out that we have to be very careful about imperialist penetrations throught the CIA amongst the youth and the students. According to one report, the Asia Foundation was asked to close down because of its CIA involvement. Sometime back, the New York Times published a series of articles, wherein, it was reported that CIA was acting through Asia Foundation, Indian youth and student organisations. Secondly, there is another body, the World Youth Assembly. This is acting through Indian Youth Assembly and it is influencing our students and youth. I do not think it is necessary to emphasise and impress upon this aspect, how the CIA, all over the world, has been trying to sabotage the progressive Govts. of the peace-loving countries and developing countries in all ways and by all means. Not only that. Through PL 480 funds, books have been published and printed at cheaper rates and at cheaper cost on all kinds of subjects, history, literature social science etc. I am sure, by these means, they want to influence our students psychologically, philosophically, which must be resented to by all.

Now, we are told that there is another foundation which is being set up in this country, called the Ford Foundation. I would request the hon. Minister not to permit the functioning of such foundations in this country and base our educational system on our own foundations.

Secondly, in the Banaras, Hindu University, I am told, RSS is allowed to hold its shackles. I think this should be stopped immediately. I do not

go to the extent of saying that this organisation should be banned immediately—though we have demanded that RSS shouud be banned—but, at least the minimum can be done to see that all such organisations are stopped from functioning in any of the University campuses.

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : वहां सी० पी० आई० की शाखा चलनी चाहिए।

SHRIMATI ROZA DESHPANDE: कोई हर्ज नहीं है। अगर वह चले, तो आर०एस०एस० से ज्यादा बढ़िया होगा।

Sir, recently, in the list of tax evaders, one name has appeared, the name of one Mr. Charles Bawes, Director of US Foundation, and this gentleman is paid annually Rs. 61,08,270. What work he does, who pays him, I do not know. He is drawing ten times the salary of our President. What work he is doing should be investigated. He has some income-tax arrears to pay.

There was a committee appionted called the Khosla Committee on the findings of the National Akamedies I would like to know what has happened to this committee.

Is it a fact that Shri A. N. Haksar, former Managing Director of Imperial Tobacco Co.—now it is Indian. Tobacco—has been appointed by the Education Ministry as the Chairman of the Board of Governors of the Kharagpur IIT? It is alleged that he has been bringing former employees of the same company and appointing them to various posts in the institute. Why he treats the institute as a tobacco company, one does not know. One can smoke but can't treat a technological institute like that. One of them, is A. N. Sharma who has been appointed by Mr. Haksar as the Chief Personnel Officer of the institute with a basic salary of Rs. 1800! The minister should enquire into this. The institute should not go up in smoke.

It was said that the Delhi School Bill adopted by Parliament will curb the activities of public schools. I would like to know how far we have done it. Private management in education has become a commercial business. I do not know what they teach in these schools. We would like to know what kind of educational system we are evolving. Let us evolve a system which we do not go on changing every time the Education Minister changes. Otherwise, it harms the children. As a mother, I hate children of 6 or 8 years carrying a cartload of books, coming back home and asking the mothers to teach them again.

The education of handicapped children should be paid more attention. A mother who has a deaf, dumb or blind child would like to see that he is educated properly. After education, what is happening is, they have to beg in the streets. When they work in the workshops, they have to go on strike for a minimum wage. Why do you teach them? Just to console because they are blind? At least they should get some wages to eat and bue. It is partly the responsibility of the Education Ministry and partly of other ministries and there should be proper coordination between them to look after this section of youth of the country.

श्री राम सूरत प्रसाद (बांसगांव) : सभापति जी, मुझे बड़ी खुशी है कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और उपमंत्री दोनों ही शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक परिवर्तनशील युग की बदलती हुई समस्याओं के अनुरूप परिवर्तन करने की दिशा में बराबर सोचते रहते है। इस दिशा में सोचने और

श्री राम सूरत प्रसाद

करने के लिए जितने धन की आवश्यकता है वह धन न मिलने के कारण उस की पूर्ति वह नहीं कर पा रहे हैं यह बात सही है। शिक्षा मंत्री जी के सम्पर्क मे संसदीय सलाहकार समिति जो शिक्षा की है उस मे रहने का मौका मिला और मैं बराबर उनके विचारों को सुनता रहा। वे हमेशा शिक्षा के क्षेत्र मे परिवर्तन की बात करते रहे। प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है उस से आज के जनतन्त्र मे हमारा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो पाएगा ऐसी भावना उन की भी रही और वह चाहते थे कि इस मे परिवर्तन हो। वह यह भी चाहते रहे कि संविधान के निर्दिष्ट सिद्धांतों की पूर्ति हेतु प्राइमरी शिक्षा पर विशेषकर 6 से 11 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाय। वह इस दिशा मे काम करने को तत्पर भी है।

मुझे शिक्षा मंत्रालय का ध्यान प्राइमरी शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों मे अमीर गरीब सबके बच्चे प्राइमरी स्कूलों के माध्यम से ही शिक्षा पाते है और उन की स्थिति यह है कि कहीं भवन है तो वहा पर अध्यापक नहीं है कहीं अध्यापक है तो वहा पर भवन नहीं है। माननीय मंत्री जी कह सकते है कि यह स्टेट सबजेक्ट है। लेकिन सारी जिम्मेदारी देश के उत्थान की उन्हीं की है चाहे स्टेट सबजेक्ट बना दें चाहे संट्रल सबजेक्ट बना दे। हम लोगों की तो इच्छा थी और सलाह भी थी कि इस को सेन्ट्रल सबजेक्ट बनाया जाये लेकिन वह कुछ कारणों से ऐसा करने मे अपने को असमर्थ पाए इस को सैन्ट्रल सबजैक्ट नहीं बना पाए। सारे देश मे प्रदेश के स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था न हो सब का उद्देश्य एक प्रकार का हो और उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा मे एक कार्यक्रम एक करीकूलम निर्धारित किया जाये तभी सारे देश का कल्याण हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पुराने जमाने मे मिडिल पास होते थे और उस की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमे अ, ब उसके बाद एक, दो, तीन, 4, फिर 5, 6, 7 और उसके बाद अंग्रेजी स्कूलों की पढाई में वह जाते थे। उस समय के जो अध्यापक थे वह इतने प्रबुद्ध थे कि उन के पढाए हुए विद्यार्थी बडे अच्छे निकलते थे और अपने कार्यक्रमों में बडे दृढ रहते थे लेकिन आज कल की जो पढाई है और जिस प्रकार के अध्यापक रखे जा रहे है उस से ऐसा लगता है कि कल्याण नहीं हो पायेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि प्राइमरी स्कूलों के जो शिक्षक हों वे अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुये हों, उनके प्रशिक्षण की भी अच्छी व्यवस्था हो और जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रदेशों मे रही है सी टी सी, बी टी सी, एच टी सी सी टी, जे टी सी आदि इन सब का समापन करके एक प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था सारे देश मे कायम करें तब कल्याण हो पाएगा और बच्चों को तभी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी जब शिक्षक इतना सक्षम हो कि वह अपने घर की चिन्ता से थोडा मुक्त रहे। उस के लिए उस का इतना अच्छा वेतन मिल सके कि उस के खान पान और रहन सहन का तौर तरीका अच्छा हो। मेरे ख्याल से उस का असर बच्चों पर भी होगा।

आप जानते है देहातों मे ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे है जो अपने मा-बाप के साथ रह कर भिन्न भिन्न वातावरण से आते हैं। उस मे अमीरों के बच्चे भी आते है, गरीबों के भी बच्चे आते है और सब को जब एक साथ रह कर पढना पडता है तो उसमें भी बच्चों की वेशभूषा और खानपान मे अंतर मिलता है तो वहीं से सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की विषमता दिखाई पडती है। इस लिए शिक्षा मंत्री महोदय प्राइमरी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे।

साथ ही सेकेन्डरी एजूकेशन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज कल जो अध्यापक रखे जाते हैं वह कौन होते

हैं ? जो कहीं नौकरी नही पाते हैं वह अध्यापन कार्य में जाते है । प्राइवेट विद्यालय वाले उन को उपयुक्त वेतन न देकर कम वेतन पर उन से शिक्षा का काम लेते है । इस का परिणाम यह होना है कि वे शिक्षा की दिशा में प्रयत्न करके उस के स्तर को जितना ऊंचा उठाना चाहिए, उतना उठा नही पाते हैं ।

यूनीवर्सिटी शिक्षा के स्तर के सम्बध में मे चाहूंगा कि आर्ट साइड पर कम ध्यान दिया जाये; साइन्स और टैकनालाजी के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये क्योंकि विज्ञान के माध्यम मे ही देश के उत्थान मे ज्यादा काम हो सकता है ।

एक बात में यह कहना चाहता हू— गोरखपुर विश्वविद्यालय मे जो विज्ञान का संकाय है, उस में लोग रिसर्च कर रहे हैं और इस प्रकार का रिसर्च कर रहे है, जो देश की रक्षा की दृष्टि से और देश मे उद्योग धन्धो को पनपने की दृष्टि से बड़ा लाभदायक होगा । मे माननीय मत्री जी से अनुरोध करूगा कि वे उस का अध्ययन करायें और उस विभाग को यू० जी० सी० से अधिकाधिक अनुदान दिलवाये ताकि वे देश के रचनात्मक कामो मे, देश के नवयुवको को लगाने की दिशा में अधिक से अधिक सहयोग दे सके ।

इन शब्दो के साथ मै इस बजट का समर्थन करता हूं ।

SHRI V. MAYAVAN (Chidambaram): Mr. Chairman, Sir, I wish to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Education for the year 1974-75.

Many of the hon. Members have spoken a lot about the medium of instruction. At the outset, I wish to refer to the policy of medium of instruction of the Central Ministry of Education. Though "Education" is in the States' sphere, the Central Government have opened Central Schools in all the States on the pretext of extending uniform educational facilities for the children of Central Government officials who are liable to be transferred anywhere in India In 1963, there were 16 Central Schools and today there are 169 Central Schools all over the country. A sum of Rs 8 23 crores has been asked for meeting the expenditure of the Central Schools in 1974-75.

The medium of instruction in these Schools is either Hindi or English. A student, if he so desires to learn his mother tongue, is permitted to take it as an optional language For example, a student reading in a Central School in Tamil Nadu can have his mother tongue Tamil as an optional language, and the medium of instruction is either Hindi or English. This is the plight of a student studying in a Central School in Tamil Nadu.

I would now like to draw the attention of the hon. Minister and also of the House to what is being done in the capital city of our country, namely, Delhi. In the Central Schools of Delhi, the medium of instruction is either Hindi or English. I need not say that in the Union Territory of Delhi, more particularly in the capital, people from all the States are living According to the Delhi Education Rules, which came into effect from 1st January 1974 in the schools started after this date which seek the recognition and aid of the Delhi Administration, the medium of instruction should be only the mother tongue or Hindi. I want to mention here that it is provided that English should not be the midium of instruction. For example, here, in Delhi, the Delhi Tamil Education Association which is already running six secondary schools in the capital having English as the medium of instruction cannot now open a new school with English as

[Shri V. Mayavan]

the medium of instruction. In such a new school, Tamil or Hindi should be the medium of instruction. In a Central School in Tamil Nadu, the medium of instruction is English. In a school which the people belonging to a State may like to start now in Delhi, English should not be the medium of instruction. For example, the Tamil-speaking residents of D.D.A. Janakpuri Colony in Delhi wanted to have a middle school in the Colony which would, in course of time, be taken over by the Delhi Tamil Education Association. But they have been told that the medium of instruction should be Tamil or Hindi and not English. Our leader, Shri Sathiyan, has moved a Resolution suggesting amendments to the Delhi Education Rules. I would request the hon. Minister to accept this amendment to the Delhi Education Rules, enabling the new schools to have English as the medium of instruction.

I need not narrate the widespread student unrest in the country. In March, 1973, a Committee was constituted to inquire into the reasons for student unrest and suggest concrete steps to redress the grievances of the students. It is regretable that this Committee proposes to meet for the first time during the course of this month. By the time this Committee submits its report the student unrest might engulf the entire country.

Similarly, when the country is being led by a madam, Mrs. Indira Gandhi, the Committee set up three years go to investigate the status of women in the country has not even begun its work. Really the hon. Minister ought to have taken action on this aspect. Perhaps, except for the chosen few, the women, both education and uneducated, are getting a raw deal from Madam Prime Minister, and the Education Ministry's Committee does not want to offend the Prime Minister by presenting a report.

A former Minister of Education, who is now the Chief Minister of West Bengal, Dr. Siddartha Shankar Ray, immediately after he became the Education Minister, announced on the floor of this House that he would formulate a National Child Policy at the earliest opportunity. But after he had left the Centre, nothing has come out and I do not know the reason for that. The lady hon. Member has stated a little while ago that, when the Minister changes, the programmes are not implemented. I wish to endorse that. If a National Child Policy is not formulated under the leadership of Shrimati Indira Gandhi, grandmother of two lovable kids, I wonder whether this will be done at all by the Central Government.

In the budget for 1973-74, a sum of Rs. 30 crores was provided for the scheme of providing employment to the educated unemployed. In this vital scheme which will save the country from the wrath of the educated unemployed, the allocation was reduced to Rs. 24 crores The Annual Report of the Ministry for 1973-74 states that no new schemes could be started with this sum. In reply to Starred Question No. 59 dated 22nd February 1974, the Finance Minister has stated that a sum of Rs. 34 crores was the saving in the employment schemes during 1973-74. If this is the manner in which the Central Government is going to tackle the student unrest, a consequence of growing unemployment. I have no doubt in my mind that the country would be aflame shortly. The half-a-million job scheme is also going to be the victim of Government's economy measures.

with these words. I conclude. I request the hon. Minister to answer about our leader's Resolution already sent to him.

श्री राम हेडाऊ रामटेक) : सभापति जी कोई भी आजाद देश अच्छी शिक्षा

के द्वारा चरित्र एवं राष्ट्र निर्माण को महत्व-पूर्ण समझता हूँ और शिक्षा के माध्यम से आत्म-निर्भरता एवं नागरिकों में देश के प्रति आदर और राष्ट्रभक्ति का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन आजादी के 25 सालों के बाद भी आज हम क्या देख रहे हैं ? हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली आज चालू है, उस को देखकर मुझे याद आता है कि मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली इस देश में जारी की थी उस को हम अभी भी नहीं भूल पाये हैं। परिणाम यह हो रहा है...

17.00 hrs.

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य को मेरा अनुरोध याद है कि एक सदस्य के लिए 7 मिनट से अधिक समय नहीं है।

श्री राम हेडाऊ : मैं 7 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

परिणाम यह है कि आज हमारी शिक्षण प्रणाली एक बेकारों का कारखाना निर्माण करने का काम कर रही है। शिक्षण में जो प्रमुख घटक है वह हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और फिर इन सब बातों का संचालन इस देश में जो शिक्षा का संचालन हो रहा है उसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्राथमिक शिक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के मातहत में चलती है लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो है उसका संचालन अधिक-तर व्यक्तिगत क्षेत्र में चल रही है और इस क्षेत्र में जो स्थिति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज शिक्षण के लिए जो पैसा हम ग्रान्ट के रूप में स्कूलों को देते हैं क्या वह पैसा शिक्षा के उत्थान के लिए वहां के शिक्षकों की पगार के लिये उचित ढंग से खर्च होता है? काला बाजार करने वाले और पैसे को भगवान समझने वाले लोग उस क्षेत्र में भी घुस चुके हैं। शिक्षा का संचालन करना उनका एक धंधा बन चुका है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां पर उन लोगों को शिक्षा क्षेत्र के बारे में बिल्कुल ही आदर नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी उन लोगों ने स्कूल खोल रखे है। उनके स्कूल में सौ सौ टीचर हैं और हर एक टीचर से, सरकारी जो वेतन श्रेणियां हैं उन वेतन श्रेणियों के हिसाब से पे-रोल पर उनके सिग्नेचर करा लिए जाते हैं परन्तु उनको कभी भी पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती है। वास्तव में जब नौकरी के लिये उनसे दर्खास्त ली जाती है उसी समय उनसे तय करा लेते हैं कि 3 सौ की पगार पर तुम से रसीद ली जायेगी लेकिन तुम्हारे हाथ में सौ रुपये दिये जायेंगे, इस शर्त पर यदि नौकरी मंजूर हो तो यहां पर नौकरी करने के लिए आईये। साथ साथ जब उनको एप्वाइंटमेन्ट आर्डर दिया जाता है तो इस्तीफा लिखाकर उसपर भी दस्तखत करा लिए जाते है। मैं समझता हूं जो गरीब लोग है वही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनते है क्योंकि जो उच्च शिक्षा पा सकता है या मेरिट का आदमी होता है वह कभी भी एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में नहीं आता। जो गरीब लोग होते है, जो लाचार होते हैं, जिनको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती है वही इस क्षेत्र में नौकरी के लिए आते हैं और उसी जगह पर उनका शोषण शुरु हो जाता है। नागपुर से एक अखबार "तरूण भारत" निकलता है जिसके 6 अप्रैल के अंक में एक प्रोफेसर भास्कर भट्ट चन्द्रपुरी ने मराठी में लिखा है :

(The hon. Member quoted in Marathi)

उन्होंने लिखा है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षकों की वेतन श्रेणियों में जो बढ़ोत्तरी की है क्या वह पैसा हमको मिलेगा ? वह शिक्षक पूछता है क्या वह जो धनराशि आने वाली है वह क्या सही माने में हमारी जेब में आने वाली है ? उसने स्पष्ट किया है कि यह धनराशि हमारे पास आने वाली नहीं है बल्कि संचालकों की जेब में ही जाने वाली है।

[श्री राम हुड्डाऊ]

यदि यही स्थिति चलती रही तो हम शिक्षकों को सतुष्ट नही रख सकते है। इस क्षेत्र मे जो शोषण हो रहा है उसको रोकना होगा। इस सम्बन्ध मे मुझे सरकार से अनुरोध करना है कि यदि आपको एक योजना कार्यान्वित करनी है, अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, गरीबो के बच्चो को अच्छी शिक्षा देनी है तो फिर आपको शिक्षण के बारे मे गम्भीरता से सोचना होगा और यह निर्णय करना होगा कि इसका सचालन किसके हाथ में रखे। आज 95 प्रतिशत पैसा ग्रान्ट के रूप मे शिक्षण सस्थाओ को दिया जाता है लेकिन वह 95 प्रतिशत पैसा उसमे लगता नही। मैं कहूगा यदि शिक्षा पर 95 प्रतिशत पैसा हम खर्च करते हैं और 5 प्रतिशत सचालको के द्वारा खर्च किया जाता है तो फिर उन शिक्षण सस्थाओ को केन्द्रीय सत्ता अपने ही हाथ मे क्यो न ले ले, उसका राष्ट्रीयकरण क्यो न हो जाये ? इसके परिणामस्वरूप बच्चो को शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और शिक्षा पर जो पैसा हम खर्च करने हैं वह पैसा भी शिक्षण सस्थाओ मे काम आयेगा।

जहा तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्राथमिक शिक्षको के प्रति देहातो मे आदर की भावना बिल्कुल नही रही है और इसके कारण वे शिक्षक अपना काम ठीक ढग से नही कर पाते हैं। देहात मे महाजन के यहा जो सालदार होता है पानी भरने वाला उसकी स्थिति और प्राथमिक शिक्षको की स्थिति बिल्कुल बराबर है। देहात मे वहा के नेता और सरपच इस ढग से उस शिक्षक की ओर देखते हैं जैसे वह उनका आदमी हो। उसको वे स्कूल से भी बुला लेते है। उनके यहा कोई मेहमान आ गया तो उस शिक्षक को उन्होंने बुला लिया। अगर शिक्षक उनके मेहमान को लोटा भर पानी देता है तो वह अपनी जगह पर काम करता रहेगा। महाजन की बीवी भी मास्टर को बुला लेती है और कहती है मास्टर साहब जरा लकड़ी फाड़ दो। मास्टर लकड़ी फाड देता है। अगर मास्टर को यह मजूर नही तो साल मे 10-15 बार उसका ट्रान्सफर होता है और उसको सताया जाता है। ऐसी दशा मे उसका क्या आदर हो सकता है। मैं ने कई जगह देखा है कि गाव का जो नेता होता है वह रास्ते मे मास्टर का अपमान कर देता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसको हमे बदलना होगा। इसके लिए मै प्रार्थना करूगा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए शासन को गम्भीरतापूर्वक कदम उठाना होगा।

इसके साथ ही मैं सक्षेप मे कुछ सुझाव देना चाहूगा। जबतक बौद्धिक और तकनीकी शिक्षा मे अन्तर्भाव नही करते तब तक हमारे यहा बेकारी बढती रहेगी। इसलिए मैं सुझाव दूगा कि 8वी कक्षा तक पूरे देश मे करीकुलम समान हो और मातृभाषा मे ही वहा पर उनको शिक्षा दी जाये। साथ साथ हिन्दी को अनिवार्य भाषा के रूप मे पढाया जाये। 8वी कक्षा के बाद एक साल तक विद्यार्थियो की जो मानसिक कल है, किस लाइन की ओर वे आकर्षित होते है उसका मनोवैज्ञानिक ढग से शिक्षको द्वारा अध्ययन किया जाये और जिन क्षेत्र मेवे आर्थिक रूचि लेते हो उसी प्रकार की शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाये। इस से जो कालेजो मे भीड हो रही है वह रूक जायगी और तकनीकी शिक्षा के कारण एक स्वय सिद्ध पुरूष इस देश मे नागरिक के रूप मे सामने आयेगा जिस से बेकारी की समस्या हल हो सकेगी।

शिक्षण क्षेत्र मे अच्छे लोग आकर्षित हो इस के लिए आल इडिया एजूकेशनल सर्विस का निर्माण करना आवश्यक है। देहातो मे गरीबी इतनी बढ गई है कि बच्चे भूखे आते हैं स्कूल मैं ने उनका अनुभव किया है और भूखे भजन न होये गोपाला। भूखा बच्चा पढाई की ओर ध्यान नही दे सकता है। तो इन गरीब बच्चो को दोपहर के भोजन की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है क्योकि नीचे के तबके के आदमी अपने बच्चो को नही

पढ़ा पा रहे ह । जब खेती का काम शुरू हो जाता है तो पिता कहता है कि स्कूल न जा, खेत में चल । नतीजा यह होता है कि बच्चे की शिक्षा बन्द हो जाती है । यदि पहली कक्षा मे 100 लडको ने प्रवेश पाया हो तो उस मे से 35 लडके चौथी कक्षा से गिर जाते है, सिर्फ 65 प्रतिशत लड़के ही चौथी कलास पास होते हैं । तो इस 35 प्रतिशत बच्चों के लिये आपको कुछ करना चाहिये ।

महाराष्ट्र शासन ने एक अनोखी बात की है । जनता ने रोटी मागी और महाराष्ट्र शासन ने सस्ते अनाज की दुकान के बजाय सस्ती दारू की दुकाने वहा खोल दी हैं, और वह स्कूल के बाहर ही गेट के पास। इसका परिणाम यह हुआ कि है 50 पैसे मे जैसे चाय नही मिलती होगी लेकिन 35 पैसे मे दारू का एक पैग मिलता है और स्कूल कालेज वाले बच्चे दारू का पैग मार कर स्कूल, कालेज जाने लग गये हैं । मेरा निवेदन है कि जितनी भी ऐसी असामाजिक तत्व है वह स्कूल के इर्दगिर्द नही होने चाहिये । कम से कम 2000 हजारफीट की दूरी पर यह दुकाने होनी चाहिये ।

जो हमारे यहा धार्मिक सस्थाये हैं, देवालय है जहा बहुत सम्पत्ति है उस का उपयोग शिक्षा के लिये होना चाहिये । वह किस ढग से करना चाहिये इस के बारे मे यदि सविधान मे सशोधन करने की भी जरूरत पडे तो सरकार और सदन को सोचना चाहिये ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चडीगढ़) : सभापति महोदय बहुत सारी बाते कहनी थी, लेकिन चूकि समय कम है इसलिये सक्षेप मे ही अपनी बात कहूगा । इस बात से मुझे बडी खुशी है कि इस समय हमारे जो शिक्षा मत्री महोदय हैं वह बडे क्रान्तिकारी विचारो के है, स्वय शिक्षा के विशेषज्ञ हैं और उन को शिक्षा का काफी अनुभव है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन के समय मे अगर शिक्षा के अन्दर जो क्रान्ति हम लाना चाहते है वह क्रान्ति अगर नही ला सके तो फिर कब ला सकेंगे । मैं ऐसा भी अनुभव करता हू कि काफी पुराना कूडा करकट जमा है जिस को साफ करना है, अगर शिक्षा के क्षेत्र मे आगे बढ़ना चाहते है । मैं नहीं कह सकता कि जिस प्रकार की स्थिति है उस मे वह कूड़े कचडे को साफ कर सकेंगे और शिक्षा को नई दिशा दे पायेंगे । इस के लिये काफी कठिनाइया उन के रास्ते मे आयेगी और मैं समझता हू कि हमे और सदन को उन का समर्थन करना चाहिये जिस से मत्री महोदय को उस कूडे कचडे को निकालने मे सहायता मिले ।

दूसरी बात यह है कि उन के रास्ते में सब से बडी कठिनाई यह है कि शिक्षा का बहुत भार प्रान्तों के हाथो मे है, वह स्टेट सबजेक्ट है । और केन्द्र के हाथ मे बहुत कम शक्तिया है । इस वजह से बहुत बाते जो वह करना चाहते है उन के रास्ते मे काफी रुकावटे आती है । मैं समझता हू हम लोग इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि आया हम शिक्षा के अन्दर क्रान्ति लाना चाहते है, उस को उपयोगी बनाना चाहते हैं, शिक्षा को वस्तुत समाज के कल्याण का साधन बनाना चाहते है ? यदि हा तो इस से बेहतर साधन और कोई नही है, और क्या यह आवश्यक नही है कि शिक्षा को कानकरेट सबजेक्ट बनाये ? कम से कम वह अधिकार जो प्रान्तो के हाथ मे है वह सेन्टर को भी दे । अभी तक काफी कठिनाइया हुई है और इस बात की आवश्यकता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते है तो सारी प्रारम्भिक और पहली आवश्यकता यह है कि हम शिक्षा को कानकरेट सबजेक्ट

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

बनाय ताकि सेन्टर सही तौर पर स्टेटस की रहनुमाई कर सके ।

हमारे यहा पर वयस्को की शिक्षा का पूरी तरह से प्रबन्ध नही है उस को महत्व नही दिया जा रहा है । उसको महत्व दिया जाना चाहिये । मै फिर कहता हू कि यह मामला स्टेट्स का है, लेकिन किस प्रकार से आगे बढे, यह कह कर कि स्टेट का मामला है, हम छुट नही सकते । जो चीज राष्ट्र निर्माण के लिये आवश्यक है उस को किस प्रकार कारगर तरीके से करना चाहिये इसका भी हमे विचार करना चाहिये । वयस्को की शिक्षा आगे नही बढ रही है, थोडा बहुत काम ही हुआ है ।

इसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम था अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा का । उस मे भी बहुत ज्यादा आगे नही बढ सके । यद्यपि कभी कभी जोर लगाते है लेकिन फिर भी ढील पड जाती है चाहे धन की कमी से चाहे साधनो की कमी । लेकिन जो एक राष्ट्र का अभियान होता है प्रोग्राम को पूरा करने के लिये उस प्रकार से आगे नही बढ सके ।

इसी प्रकार से काफी चर्चा थी आजादी के बाद बेसिक शिक्षा की शिक्षा की रकम हम प्रारम्भ म बदलना चाहते थे, यानी प्रारम्भिक शिक्षा का ऐसा रुप करना चाहते थे कि विद्यार्थी एक्टिविटी के साथ जैसे काम कर उस के साथ साथ उस की शिक्षा हो और उस पर महात्मा गाधी ने काफी सहयोग दिया था । हमारे बहुत से शिक्षा शास्त्री इस दिशा मे बहुत कुछ करते रहे लेकिन वह तमाम शिक्षा, बेसिक शिक्षा अब समाप्त हो गई है । मुझे खुशी होती अगर बेसिक शिक्षा हमारी सफल नही हुई तो कोई और परीक्षण करते जिस से शिक्षा को क्रिया के साथ, एक्टिविटी के साथ शिक्षा को मिला सकते । लेकिन कोई नई चीज नही ला सके बेसिक शिक्षा को भी खत्म कर दिया । मै समझता हू कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी की प्रणाली पर कायम है । एक यान्त्रिक तरीके से हमारी शिक्षा चलती है उस मे हम कोई परिवर्तन नही कर पाये ।

विगत 26 साल मे कितने ही शिक्षा कमीशन बैठे और उन्हो ने प्रारम्भिकम माध्यमिक और उस के बाद उच्च शिक्षा के सम्बन्ध मे बडे अच्छे अच्छे सुझाव दिये । लेकिन उन मे से किसी पर भी हम काम नही कर सके । शिक्षाप्रणाली परपजलैस है जिस की वजह से बेकारी है । इस समय बहुत सारी राष्ट्रीय समस्याये शिक्षा प्रणाली से पैदा हुई हैं और उन का हल भी शिक्षा मे ही है – चाहे अध्यापको की शिक्षा हो, चाहे विद्यार्थियो की शिक्षा हो ।

हमारे विश्वविद्यालयो मे शिक्षा का वातावरण नही हैं बल्कि एक प्रकार से वहा पौलिटिक्स चलती है और वह राजनीति के अड्डे बन गये हैं या विदेशी षडयन्त्रकारियो के अड्डे बन गये है । मैं समझता हू कि विद्यार्थियो मे जो विद्रोह की भावना है उस के कई कारण हैं लेकिन उस विद्रोह की भावना को विदेशी लोग राजनीतिक दिशा से प्रेरित कर रहे है और इस का कारण यह है कि विदेशी षडयन्त्रकारी हमारे शिक्षा के क्षेत्र मे घुस गये हैं । हमारी शिक्षा के क्षेत्र मे साम्प्रदायिक विरोह काफी घस गये हैं उन का भी बहुत हाथ है जो विद्यार्थियो को कम्युनल रास्ते पर डालते है । तो यह सब शक्तिया जो राष्ट्र की प्रगति मे बाधा पैदा कर रही है उन का जमाव शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहा है । हम विवेचन करे कि कौन व्यक्ति वहा पर है किस प्रकार के व्यक्ति वहा पर आते है किस प्रकार की शक्तिया काम करती हैं । इन सब बातो से बहरे हो कर हमारी तमाम शक्ति एक यन्त्र को चलाने मे लगी हुई है । लेकिन उस मे से क्या निकला है और क्या उस का उद्देश्य है और किधर वह

हम को ले जा रहा है इस तरफ हम तवज्जह नहीं दे रहे हैं।

हम शिक्षा प्रणाली से कोई परिवर्तन नहीं कर सके। कहीं भी कनवोकेशन एड्रेस हो, बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रीयों के भाषण हो, हर एक वही कहता है कि आजकल की शिक्षा त्रुटिपूर्ण है और उसको वे कंडेम करते है; उसकी कन्टेंट पूरी नहीं है, उसके अन्दर बहुत कुछ सुधारों की गुंजाइश है लेकिन इस बारे में कुछ किया नहीं गया है। आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार के सुधारो की आवश्यकता है और उनको आप करे। साथ ही साथ हम को उन समस्याओं का भी हल निकालना है जो नई नई पैदा हो रही है, जैसे छात्रो की समस्याये है, अध्यापको की हैं, प्राइमरी शिक्षा की है। आप किसी भी प्राइमरी स्कूल मे चले जाए, देहात के प्राइमरी स्कूल में जाए, शहर के प्राइमरी स्कूल मे जाएं, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल मे जाए और वहा बच्चा जिस प्रकार मे रहता है, जिस प्रकार चलता है, बैठता उठता है इसको देख कर आप घबरा उठेगे, जो व्यक्ति भी बच्चो को प्यार करता है व्यक्ति जो बच्चो को ठीक प्रकार मे रखना चाहता है अपने बच्चो को उन स्कूलो मे वह भेजना नही चाहेगा। इसका आप दूसरे देश के स्कूलो से मुकाबला करे। वहा जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करते है, उनके साथ इन बच्चो का मुकाबला करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी हमारे मे कमी है और ये जो कमिया है इनको आप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं इतिहास की शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इतिहास जो पढ़ाया जाता है उस में साम्प्रदायिकता का विष घुसा हुआ है। अंग्रेजों ने जो इतिहास तैयार कराया उस में उन्होंने कूट कूट कर विष भरवाया, साम्प्रदायिकता का विष और उसी को हम अपने बच्चों को पढ़ाते जाते हैं। उन्होंने इस तरह की भावना बच्चों में पैदा करने की कोशिश जैसे हमारा तमाम इतिहास की जो है वह साम्प्रदायिक झगड़ों से भरा पड़ा है, अत्याचारों की कहानियों से भरा पड़ा है, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर अत्याचार ही अत्याचार करता रहा है। इस तरह जो चीज है इसको हम इतिहास की किताबों में से दूर करवाएं। मुझे खुशी है कि आपने इस दृष्टि से इतिहास की पुस्तकों में सुधार लाने का प्रयत्न किया है। लेकिन अभी भी विशेषकर प्रान्तों में और यूनिवर्सिटियों में जो पाठय पुस्तके रखी जाती है उन में कही किसी न किसी प्रकार से यह बात आ जाती है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

हम को शिक्षा के सवाल को एक बहुत अहम सवाल समझना चाहिये और क्रान्तिकारी परिवर्तन इस में लाने चाहिये। जो क्रान्ति हम अपने देश मे लाना चाहते है वह शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है और किसी प्रकार से नही।

सभापति महोदय : थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि समय की कमी है इस वास्ते 6—7 मिनट से ज्यादा कोई माननीय सदस्य न ले। लेकिन अब वह सीमा और भी घट गई है। अब बाकी जो सदस्य है उन्हे दो दो मिनट से अधिक नहीं मिल सकते हैं। मैं खड़ा हो जाऊंगा और दूसरे सदस्य को पुकारूंगा। इस शर्त पर माननीय सदस्य बोलने की कृपा करें।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : दो मिनट मे तो प्वाइंट भी नहीं रखे जा सकते हैं।

सभापति महोदय : एक या दो विषय बिन्दु दो मिनट में अच्छी तरह से कहे जा सकते हैं।

SHRI MADHURYYA HALDAR (Mathurapur): The Minister can reply tomorrow.

MR. CHAIRMAN: That is not possible.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the demands. For want of time, I shall not make a long speech. I had asked a question to the ministry whether Government has any proposal to develop the tribal scripts. Santhali and Savara? The Hon'ble Minitser replied that they have information about the OL script in Santhali language but they have not information about the Savara script.

Article 29(1) of the Constitution provides for the development of any language or script of any community. I would like to submit SAVARA script book for the consideration of the Minister the question of the development of the Savara script.

There are nearly 1300 different dialects and languages in the country. There are about 62 different tribes in Orissa. They have got different dialects. They could not understand each other's language and dialects. Here we speak about development of tribal education. This being the position, how can we develop eduaction among the tribals?

My submission is that the private colleges which come under the Scheduled areas and Scheduled Tribal districts should be taken over by Government. The primary schools and the secondary schools which are the foundation for eduaction of the tribals should all be taken over by the State Government. (*Interruptions*).

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Please give him some more time especially because he is referring to the tribals.

MR. CHAIRMAN: It is not just possible today. I have every sympathy for him, but it is just not possible.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Secondly, the Minister in charge of culture replied to my question that Government will develop the tribal culture. I would submit to the hon Minister that the Government should have a National Institute of Tribal Culture for the cultural development of the tirbal people.

My third submission is that there should be a Rural Institutes for the development of language and training of the tribal studetns. Lastly, because the time is very short,—I was waiting and waiting to speak something—I will just mention one thing and conclude. You know, in the august House, and everywhere we are deprived of the opportunity to apeak about our grievances and put them before the Government and the Parliament. I am not angry that I could not get the time. But the point is this. You know the tribals have language but they have no voice to put the grievances. They sent us to speak but we cannot get the time to speak. Lastly, Sir, I want to submit before the Government that they should consider the development of our tribal language and education.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Chairman Sir. I do not want to take much time of the House, and I will be very brief.

The Gujarat Government had taken a decision to establish a residential university, namely, the Bhavnagar Residential University, at Bhavnagar. I think a Bill to this effect has also been passed, but the Government could not implement the decision or it has failed to implement the decision if I may say so. Now, as you know, the State of Gujarat is under President's rule, which means practically it is under Central rule and therefore, I want to bring this matter to the notice of the hon. Minister and I would appeal to him. As the Gujarat Government has passed the Bill to establish a residential university, namely, the Bhavnagar Residential University, at Bhavnagar, the Government should come forward and implement the decision without any loss of time.

I may add that the people of Bhavnagar district as a whole are very sensitive over this question, and therefore, I suggest that the hon. Minister should attend to it immediately and implement the decision taken by the Gujarat Government to establish the Bhavnagar Residential University.

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : अन्त में जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं आपका ध्यान प्राइमरी स्कूलों की ओर ले जाना चाहता हूं। इन स्कूलों की खास कर गावों में स्थिति बहुत ही खराब है। उनके लिए अभी तक भवन नहीं बन सके है। कुछ दिन पहले उनके लिए भवन बनाने के लिए, एक कोठरी के मकान बनाने के लिए आपने 1300 रुपये प्रति कोठरी हिसाब से स्वीकृत किए थे। अब इतने पैसे में कोई मकान नहीं बन सकता है। मैंने देखा है बिहार में एक मकान के लिए दो हजार रुपये का एस्टीमेट दिया गया है। इस एस्टीमेट में ईंट की कीमत 60 रुपये प्रति हजार लगाई गई है। बिहार में इस वक्त 115 से 120 रुपये प्रति हजार के हिसाब से ईंटे बिक रही है। मेरा निवेदन है कि यह जो एस्टीमेट है यह रिवाइज होना चाहिये, दूसरा बनना चाहिये और यह इतना होना चाहिये ताकि मकान उसके अन्दर बन सके। जो वर्तमान कीमते है उनको ध्यान में रखते हुए ग्रांट आपको बढ़ानी चाहिये।

मैं पांच मिनट आप से लेना चाहता हूं।

स्पोर्टस ग्राउन्ड्स के डिवेलेपमेंट के लिए देश के हर एक जिले में आपको दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत करनी चाहिए।

देश में जो सैंट्रल स्कूल हैं वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या कम से कम पांच सौ होनी चाहिए और नए सैंट्रल स्कूलों की स्थापना होनी चाहिये।

जो पोलिटिकल सफरर है जिन्होने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और कइयों को फांसी भी हुई, उनके बच्चों के लिए आपको देश में जो पांच आई आई टी है उन में बिना किसी किसी डिविजन का ध्यान किए हुए मार्क्स आदि का ध्यान किए हुए एडमिशन देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अलावा देश में जो मेडिकल कालेज तथा अन्य कालेज है उन में भी पोलीटिकल सफरर्ज के बच्चों को एडमिशन देना चाहिए और बिना डिविजन या मार्क्स का खयाल किये उन को इस बारे में प्रेफरेंस देनी चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें—श्री नूरूल हुडा।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, केवल दो मिनट और।

MR. CHAIRMAN: Your speech will not be recorded if you go on.

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, जब आप ने दूसरे सदस्यों को पद्रह और बीस मिनट तक दिये है तो आप मुझे पाच मिनट क्यों नहीं देते? आप यहां भी समाजवादी व्यवस्था लाइये। आप को टाइम का रिकार्ड रखना चाहिए। आप को समय देना पड़ेगा। आप मेरे साथ इस तरह इनजस्टिस न कीजिए।

MR. CHAIRMAN: You take it up with your own party. You cannot ask the Chair.

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं बोलूंगा। आप रिकार्ड करायें या

[श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव]

नहीं, मैं बोलूंगा आप जानते हैं कि इलैक्शन पेटीशन के संबंध में मेरे दो बरस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग गये लेकिन फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं होता है।

MR. CHAIRMAN: All right. the hon. Member may conclude in one minute.

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : : स्कूल आफ़ बिज़िनैस मैनेजमेंट पटना में खोला चाहिए।

प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए, जिस हिसाब से कालेज के शिक्षाकों का वेतन बढ़ाया गया है।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान उत्तर बिहार में सीतामढ़ी की ओर ले जाना चाहता हूं। सीतामढ़ी माता सीता की जन्मभूमि है। वहां पर नेहरू युवक केन्द्र शीघ्रातिशीघ्र खोलने की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, आप ने मुझे टाइम दिया उस के लिए धन्यवाद।

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): Mr. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the Education Minister to the fact that recently, the Government of Assam have introduced a syllabus, on the strength of which, the linguistic minorities of the State of Assam such as the Bodo people, the Manipuri speaking people as well as the Bengali speaking people all over the State—especially, in my district, the Bengali speaking people constitute about 80 per cent of the population—have to learn Assamese as a compulsory language which was not there for the last 26 or 27 years. If this syllabus is introduced compusorily, in all the schools where linguistic minorities study, it would create more confusion, bitterness and a feeling of animosity would be generated. So, I would request the Education Minister to persuade the State Government and ask them not to impose Assamese language as a compulsory subject in all the schools. Rather, we propose, Assamese may be introduced as an optional subject. We have noillwill or grudge against the Assamese language and if it is introduced as an optional language, people belonging to the linguistic minorities would be able to learn Assamese language and moreover, the introduction of Assamese language as a compulsory subject would debar the linguistic minorities from learning Hindi, which is the official language of the whole Indian Union. Since I have not much time, I would request the Education Minister to consult the State Government and take necessary steps to see that this discriminatory attitude on the part of the State Government is put a stop to

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Sir, before I start my speech I would like to express through you my apologies to my revered and distinguished friend, the honourable Shri Samar Guha. I do not remember what honorific I used, but if I used an honorific which appeared to be derogatory to him, I withdraw it and apologise most sincerely. I think he is a public man of such eminence that an honorific is not really relevant to him. I may disagree with my friends, but I do not want them to feel that I am lacking in respect or regard for them, particularly my friends on the opposite side.

I would like to express to my hon. friends on all sides of the House my very deep sense of gratitude for the keen interest they have shown for the progress of education, social welfare and culture in the country. They have made extremely valuable and enlightening suggestions. I can assure them that I shall go through the record of their speeches with great care and wherever possible, I shall try incorporate in our programme

their suggestions. Because of this keen interest shown by the hon. Members and the fact that the debate has gone on for full two days, I may not be able to touch on every point, but I hope I will be forgiven for not referring to each point separately.

Last year was rather difficult for my Ministry. As the House is aware, the draft five-year plan proposals were finalised early in June last. Our original idea was to utilise the year 1973-74 to taking advance action so that the plan implementation should begin from the very beginning of the fifth plan period. But because of the economy drive, we lost the funds that we would have ordinarily got for advance action. Our plan allocation was cut by about Rs. 10 crores and we had to struggle hard to see that the work was as little affected as possible. We have done our best to get acceptability of the programme, to formulate the programme, to plan a course of action which I hope will enable us to start implementing the programme very soon indeed.

I entirely share the sense of disappointment expressed by several hon. Members at the reduction in our allocations. In view of this, many of the schemes have had to be given up, priorities altered and phasing undertaken. But I am still hopeful that we might be able to persuade the powers that be to give consideration to some of the more urgent programmes. However, even though our allocations have had to be reduced because of the economic constraints and difficulties with which the country is faced, I think it is a challenge to all of us who are in the field of education. We cannot give up our objectives; it is our duty to implement them. If funds are inadequate, we have to work out new strategic and new ways because we cannot ignore the needs and requirements of the newer generations and the urgent necessity of investing in the manpower of the future; I am not using the term "manpower" in the limited economic sense but in the sense of the progress and development of the country.

During this time the formulation of our plans is more or less over and implementation has started. We have initiated action on some of the programmes such as the third educational survey, the transformation of the primary education system, the introduction of a uniform pattern, the vocationalisation of education at the higher secondary stage, the regulation of enrolment in full-time higher education and programmes of its qualitative improvement. In the course of this year we will develop these programmes further and initiate several others. It is our hope that by the end of this year the Fifth Plan should be in full swing.

Several hon. Members have emphasized the importance of primary education. This is a view which we subscribe to fully. I realise that the allocation for primary education is not as much as we had hoped for. Originally, the National Development Council had given us about Rs. 1,100 crores for primary education which is about 50 per cent of the total Plan outlay. This had to be reduced to Rs. 743 crores. Even this is now in the Minimum Needs Programme sector and, therefore, I hope the money will be available. The percentage is 43, which is the highest for elementary education sector when compared to any of the earlier plans so far, and it is more than three times what had been provided for in the Fourth Plan, which was Rs. 239 crores. I would further like to submit that it is not the size of the outlay, but the manner in which this outlay is going to be utilized, which is going to influence the course of elementary education.

Several hon. Members have referred to drop-outs, to the fact that there are many sections of our population, particularly, the Scheduled Castes and Tribes, women and other

[Prof. S. Nurul Hasan]

weaker sections of the community where the percentage of drop-out is very large indeed. Therefore, no programme of primary education is likely to meet the requirements of the case unless this problem of drop-out is squarely tackled. We have, therefore, decided that the single-point entry should be modified and that we should be prepared to make arrangements for multiple entry; that is to say, apart from entry in the 6 to 7 age group, there should be further entry at 9 to 11 and 12 to 14 age groups, part-time education and informal education. We are also providing incentives to the children of the weaker sections of the community so that they may be able to benefit from school education. I am not going into the details because of shortage of time. If the hon. Members would care to see the proceedings of the Central Advisory Board of Education and of its Standing Committee, they would find out the main outlines of this programme.

I would like to inform the House that the targets to be achieved at the end of the Fifth Plan are much above the levels reached at the end of the Fourth Plan. The enrolment in the age group of 6—11 will increase from 84 per cent in 1973-74 to 97 per cent in 1978-79 and in the age group from 11—14, the enrolment will increase from 36 per cent in 1973-74 to 47 per cent in 1978-79 In addition, we propose to enroll 78 lakhs additional children in the courses of non-formal education. At the end of the Fifth Plan, therefore, we might reach the enrolment of 75 per cent in the age group of 11—14. Although we have not been able to fulfil the constitutional directive as envisaged in article 45 of the Constitution, we hope that within the Sixth Plan period, the objective would be achieved.

Let me inform the House that we did take a few measures to help increasing enrolment in primary education towards the end of the Fourth Plan period. When we found that owing to financial difficulties the State Governments were not in a position to appoint the necessary number of teachers, we sanctioned 76,000 additional teachers under various schemes. These teachers were utilised to open new schools in school-less villages and to improve the pupil-teacher ratio in others. In addition, we sanctioned 97,000 teachers under the other scheme of half a million jobs. This substantial assistance gave the boost to enrolment at the primary stage.

We have also attempted side by side to have quality improvement programmes. The National Council of Educational Research and Training in collaboration with the State Institutes of Education in the States and the National Staff College in collaboration with the District Education Officers have been taking up various programmes of quality improvement. The content of education and its changes in the curriculum are extremely important and by no means less important than expansion of the facilities of education. I am happy to inform the House that the preliminary work which has been done by the N.C.E.R.T. towards curriculum improvement is of a very high order. A Special Committee under the Chairmanship of the Director of the NCERT has been examining the question and, we hope, the new curriculum will be available shortly We hope to make this curriculum available to State Governments so that they have it examined by their State Institutes of Education and by other educationists.

SHRI SAMAR GUHA: Before finalisation, certain experiences of teachers should also be considered.

PROF. S. NURUL HASAN: Yes. As my hon. friend mentioned, we have evolved the school teachers' organisation both at the secondary level

and the primary level. Apart from the fact that refresher courses are given to them....

SHRI SAMAR GUHA: Some seminars may also be organised.

PROF. S. NURUL HASAN: The seminars are being organised. They have already been organised. I entirely agree with what my hon. friend has said. I think, without involving school teachers, this programme will not become as meaningful as we hope it would.

Many hon. Members have spoken of basic education. We still subscribe to the ideal of basic education. We realise that because of certain shortcomings...

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Without allocation.

PROF. S. NURUL HASAN: I thought when Gandhiji put forward the concept of basic education, he was not thinking in terms of allocation.

PROF. MADHU DANDAVATE: Poor Gandhiji!

PROF. S. NURUL HASAN: There were some difficulties. We are now devising ways and means to overcome those difficulties. But the basic idea is very much acceptable to us still and is guiding us in our policies. For this purpose, we have already sanctioned 1,000 school teachers for introducing work experience in selected middle schools. The programme will be expanded by the State Governments under the Fifth Plan. Work experience at the secondary schools is also being emphasised, and attempt to inculcate a sense of dignity for manual labour is very much there.

The question of examination reforms has been mentioned here. Both at the school as well as tertiary level, attempt is being made to introduce examination reforms. Many institutions of higher learning have adopted the various proposals of the UGC and of the other Committees in regard to examination reforms. Some of the State Governments have already introduced the recommendations of the CABE Committee on examination reforms...

SHRI MADHURYYA HALDAR: Which are those States?

PROF. S. NURUL HASAN: I can straightaway mention Tamil Nadu. I think, Maharashtra has also done it. I read the reports of these two States recently, and I think that the programme of evaluation which they have introduced in consultation with the NCERT is a very interesting programme.....

SHRI SAMAR GUHA: Give us a resume of the work done there—on examination reforms. That will be interesting.

PROF. S. NURUL HASAN: I wish I had time to do it. I would like the hon. Members to be good enough to write to me, and I will supply them the information in this regard because I think the country ought to know that work on this has started; at least it has been initiated.

Some hon. Members have referred to shortage of paper. I share the concern of the hon. Members....

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): Share the stocks of paper and not only the concern.

PROF. S. NURUL HASAN: We have some stocks which we are sharing. We were able to get some stocks from UNICEF and some friendly Governments, and those are already being supplied to the various State Governments for the publication of school text-books. We have been working in close contact with the Ministry of Industrial Development, and steps have been taken to bring down the

[Prof. S. Nurul Hasan]

price of paper and for increasing the manufacture of printing and writing paper. The Ministry of Commerce have stopped the export of printing and writing paper. We are in constant touch with the nationalised text-book boards as well as with the federations of printers and booksellers and stationers, and all possible steps will be taken to see that, if the shortage of book is not eliminated, at least the hardship is minimised.

Many hon. Members referred to the importance of text-books in schools, particularly from the point of view of national integration, as also for inculcating a scientific outlook among the people.

The House will recall that when Prof. V. K. R. V. Rao was the Minister of Education, he had initiated a programme of crash evaluation of school text-books So far, 3,000 books have been screened and final reports regarding books in 15 States and Union Territories have been sent to the parties concerned. Most of our recommendations have been accepted by the State Governments. Some action has already been taken to implement these recomendations and I hope that it will be possible for us to persuade the State Governments that those recommendations which have been accepted by them should be implemented as quickly as possible. Now, the review of text-books will be a continuous process and all types of schools whether affiliated to the State Boards or schools like those affiliated to the Council of Indian School Certificate will also be reviewed by the NCERT.

As regards scientific approach and science education in our States—this was referred to by an hon. friend of mine who thought that in rural areas this was not being done. I can assure him that the School Science Programme has been taken up by us in right earnest, as well as the production of science books, science kits, popularization of science fairs and science exhibitions and so on. These books have been translated into local languages and tried out in about 1100 schools in the country. We are now in a position to have these introduced in a very large number of schools throughout the country. There is also a scheme to have a mobile science laboratory in every district and this is being finalised.

Many hon. Members have rightly and correctly emphasized the question of educational opportunities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. Again, I would say that I entirely share this concern. But this specific subject is now being transferred since last year to the Ministry of Home Affairs and I understand...

SHRI MADHURYYA HALDAR: Then transfer your share also.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is being mis-managed by the Home Ministry.

PROF S NURUL HASAN: I understand that the Home Ministry has decided that the quantum of scholarships should be raised (*Interruptions*) It is only fit and proper that my colleague here .

श्री मधु लिमये : आप के बगल में बैठे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): The proposal is to increase the scholarship by 50 per cent at least, for both categories

श्री मधु लिमये : लेकिन 15-4 परसेन्ट कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ऊपर उठा है।

PROF. S NURUL HASAN: We are having sub-plans within the educational sector for the weaker sections of the community.

In so far as the Indian Institutes of Technology are concerned, the House will be glad to know that we have succeeded in...

MR. CHAIRMAN: I am sorry, the hon. Minister will allow me to interrupt him. The Foreign Minister is to make a statement.

The Foreign Minister.

18.00 hrs.

STATEMENT *RE.* BANGLADESH-INDIA-PAKISTAN AGREEMENT

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): I have the honour to lay on the table of the House, the text of the Bangladesh-India-Pakistan Agreement, signed in New Delhi on April 9, 1974. This Agreement is the culmination of our efforts since the end of the conflict in 1971 to bring about a resolution of all humanitarian issues arising out of the events of 1971 through bilateral and peaceful means. As the House is aware, India undaunted by the difficulties and obstacles, continued to take repeated initiatives, in consultation with the Peoples Republic of Bangladesh, so that today India and Bangladesh can say with some satisfaction that our efforts have borne fruit. The three countries of the subcontinent have reached the threshhold of reconciliation. This is largely due to the enlightened statemanship of the Prime Minister of Bangladesh, India and Pakistan who were prepared to work for mutual accommodation and reconciliation in the larger interests of their people. In this context India's well-known stand advocating the establishment of harmonious and peaceful relations between the three countries of the sub-continent based on mutuality of interest and equality has been amply vindicated.

In April, 1973 Bangladesh and India took the initiative of issuing a Joint Declaration delinking the political questions from the resolution of humanitarian issues This was a major step forward to break the deadlock, existing at that time due to the non-recognition of Bangladesh. Following the Declaration, India again took the initiative to hold a series of talks with Bangladesh and Pakistan which ultimately resulted in the Delhi Agreement of August 1973. This Agreement has already enable nearly 300,000 people to return to their homes. Almost all the Banglees in Pakistan, who wanted to return to Bangladesh have been repatriated, 84,000 Pakistani Prisoners of War and civilian internees have been repatriated by India while over 90,000 Pakistan nationals from Bangladesh have so far been cleared for repatriation to Pakistan. In accordance with the recent Tripartite Agreement, Pakistan has reiterated that all those Pakistanis in Bangladesh who fall in the specified categories would be received by Pakistan without any limit as to numbers, and that the rejected cases would be subject to review between the Governments of Pakistan and Bangladesh. This Agreement brings about a final and mutually agreed solution to the humanitarian problems arising out of the conflict of 1971.

The question of 195 prisoners of war has been resolved to the mutual satisfaction of both Bangladesh and Pakistan Governments and we welcome this development. This decision, is in the larger interests of the 700 million people of the three countries and signifies the resolve of their Governments to work for the promotion of normalisation of relations and establishment of durable peace in the sub-continent.

I am also placing on the table of the House the text of a bilateral Agreement between India and Pakistan on the release and repatriation of pre-war detainees and the text of a Joint Communique. The Agreement on the release of pre-war detainees denotes an important step which will bring about and end to the continued